पेज-6 विधायक सुनील शर्मा व नंदकिशोर गुर्जर ने साधे एक तीर से दो निशाने

दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर व उत्तर प्रदेश से एक साथ प्रसारित

विशेष खबर

खबरों पर गहरी नजर

मीडिया समूह का समाचार पत्र, न्यूज पोर्टल व यूट्यूब चैनल आपकों बनाएगा
सिटीजन जर्नलिस्ट

आपकी लेखनी में धार है, आवाज में खनक है या आपके पास ऐसे मुद्दो व खबरों को परखने की समझ है जो किसी सच से परदा उठा सके या किसी की मदद कर सकें तो आप विशेष खबर मीडिया ग्रुप से जुड़कर बन जाइए सिटीजन जर्नलिस्ट

call or Msg: 9711345310- 9868561056
प्रधान संपादक: विनीतकांत पाराशर

Follow us on @VisheshKhabartv www.visheshkhabar.in @visheshkhabar6115 9711345310

वर्ष: 6 अंक: 28 | हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र | गाजियाबाद, 13-19 नवंबर 2023 | visheshkhabar.tv@gmail.com | RNI NO :UPHIN/2017/74151 | पृष्ठ: 6 मूल्य: 5 रूपये

अन्दर के पेजों पर
2 संपादकीय: क्या है राजनीतिक दलों के चुनावी गारंटियों के लॉलीपॉप का अर्थशास्त्र ?
3 17 से 20 नवंबर तक मनाया जाएगा उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक आस्था का छठ महापर्व
4 प्रगति मैदान में सज गए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के मंडप, 27 नवंबर तक चलेगा
5 47 साल की विकास यात्रा में ऐसे बदल गई गाजियाबाद की सूरत

सभी पाठकों को
भाई-बहन के प्रेम व सर्मपण के प्रतीक पर्व भाई दूज
लोक आस्था के चार दिवसीय छठ महापर्व
की हार्दिक शुभकामनाएं

विनीतकांत पाराशर
प्रधान संपादक

सार समाचार

दिल्ली वाले दीवाली से पहले 17 दिन में गटक गए 525 करोड़ की शराब

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। दिल्ली में दिवाली के त्योहार के दौरान शुक्रवार से रविवार तक लोगों ने करीब 121 करोड़ रुपये मूल्य की 64 लाख शराब की बोतलें खरीदीं। उन्होंने बताया कि आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिवाली से एक हफ्ते पहले एक करोड़ से अधिक शराब की बोतलों की बिक्री से सरकार को 234.15 करोड़ रुपये की कमाई हुई. जबकि पिछले 17 दिनों के दौरान कुल 525 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हुई।

दिल्ली आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक दिल्ली में होली और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री बढ़ जाती है क्योंकि इसे न केवल व्यक्तिगत उपभोग और भंडारण के लिए खरीदा जाता है बल्कि उपहार के रूप में देने के लिए भी खरीदा जाता है।

3 दिनों में बिकी 64 लाख शराब की बोतलें

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार दिवाली से पहले 17 दिनों में कुल बिक्री तीन करोड़ बोतलों से अधिक थी, जिससे दिल्ली सरकार को 525.84 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। दिवाली से ठीक पहले शराब की बिक्री में तेजी आई और बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को दुकानों पर क्रमशः 17.33 लाख, 18.89 लाख और 27.89 लाख बोतलें बिकीं। उन्होंने बताया कि दिवाली पर शराब की दुकाने बंद रहीं।

2022 की तुलना में काफी ज्यादा हुई हुई शराब की बिक्री

आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तीन दिनों में 64 लाख से अधिक बोतलों की संयुक्त बिक्री से दिल्ली सरकार को कुल 120.92 करोड़ रुपये की कमाई हुई। उन्होंने बताया कि पिछले साल दिवाली से तीन दिन पहले शराब की बिक्री क्रमशः 13.46 लाख, 15 लाख और 19.39 लाख बोतलों की हुई थी। साल 2022 में दिवाली से पहले के 17 दिनों में दिल्ली में 2.11 करोड़ शराब की बोतलें बेची गईं। इस लिहाज से इस साल बेची गई बोतलों की संख्या करीब 42 प्रतिशत अधिक है।

पीएम मोदी ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। देशभर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 14वीं किस्त का लाभ मिलने के बाद से देशभर में कई किसान लंबे समय से 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। उनका यह इंतजार अब खत्म हो चुका है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर खूंटी, झारखंड से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त जारी की । देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के खाते में 2 हजार रुपये की इस राशि को डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया गया । देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। इसके अलावा पीएम किसान पोर्टल पर भी इसको लेकर अपडेट जारी हो चुका है। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए।

अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में आपको योजना में अपनी ई-केवाईसी करानी जरूरी है। अगर आप योजना में अपनी ई-केवाईसी नहीं कराते हैं। ऐसे में आपके खाते में 15वीं किस्त के पैसे नहीं आएंगे। अगर आपने यह काम अभी तक नहीं कराया है। ऐसे में आपको जल्द से जल्द इस जरूरी काम को करा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भूलेखों का सत्यापन कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

नीतिश के बयान पर सियासी बवाल

पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया करते 'अज्ञात दोस्त'

इस साल पाकिस्तान में भारत के खिलाफ जहर उगलने व जेहाद छेड़ने वाले 16 आतंकियों की रहस्यमय हत्या

सुनील वर्मा @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में भारत के 'अज्ञात दोस्तों' की संख्या बढ़ती जा रही है। ये 'अज्ञात दोस्त' जिस तेजी से भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं उससे पाकिस्तानी सेना के पैरों तलों से जमीन खिसक गई है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को समझ नहीं आ रहा है कि अपने पाले-पोसे आतंकवादियों की सुरक्षा कैसे करे। कभी यही आतंकवादी भारत के लिए सिरदर्द साबित होते थे, वे जहां चाहे आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर निर्दोष लोगों की जान ले लेते थे। आज उन्हीं आतंकवादियों के जान लाले पड़ गए हैं।

रविवार को जब भारत में लोग रोशनी के पर्व दीपावली का जश्न मनाने के लिए आतिशबाजी कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानी के करांची शहर के ओरंगी टाउन में अज्ञात लोगों ने मशहूर धार्मिक नेता मौलाना रहीमुल्ला तारिक की गोली मारकर हत्या कर दी। धर्म की आड़ में आतंकियों की फौज तैयार करने वाले और भारत के खिलाफ जहर उगलकर हजारों लोगों का ब्रेनवॉश करने वाले मुल्ला को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती थी।

बीते 5 नवंबर को जम्मू में आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड ख्वाजा शाहिद मारा गया था और अब एक सप्ताह के भीतर भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। पाकिस्तान में भारत विरोधी भाषण देने वाला और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लश्कर आतंकी अकरम खान गाजी को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पाकिस्तान में इस साल अब तक भारत के 17 दुश्मनों का सफाया किया जा चुका है। वहीं 2022 में पांच भारत विरोधी आतंकवादी मारे गए थे।

ये नया भारत है, एक-एक कर मरते जा रहे आतंकवादी

पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह भारत का कद बढ़ता जा रहा है, वह विदेशी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा है। इसीलिए वे तरह-तरह के प्रपंच कर भारत को बदनाम करने, उसकी विकास की रफ्तार को रोकने के षडयंत्र में जुटे हैं। लेकिन यह नया भारत है, भारत के दुश्मन जहां कहीं भी हो उसका खत्म होना निश्चित है, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। 2014 से पहले की सरकारें आतंकवादी हमला होने पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका जैसे देशों से निहारा करती थीं कि

वे इसकी निंदा करें और भारत को इन आतंकवादी हमलों से बचाएं। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इस कदर सशक्त, सबल और सक्षम हुआ है कि अब वह दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देता है। यही वजह है कि अब भारत नहीं, पाकिस्तान खुद को आतंकवाद से पीड़ित बता रहा है।

पिछले कुछ समय में भारत विरोधी जो आतंकवादी विदेशी धरती पर मारे गए हैं। उन पर एक नजर डालना जरूरी है।

9 नवंबर 2023 को भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले लश्कर आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गाजी ने साल 2018 से 2020 तक लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। वह पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भड़काऊ बयानों के लिए के लिए जाना जाता था। अकरम लश्कर-ए-तैयबा का पूर्व कमांडर था।

5 नवंबर 2023 को पीओके में भारत मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी ख्वाजा शाहिद उर्फ मिया मुजाहिद की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर कटी लाश बरामद की गई। ख्वाजा साल 2018 में जम्मू के आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड था। जिसमें 6 जवान, एक सैन्य अधिकारी और एक आम नागरिक की मौत हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों को काफी समय से उसकी तलाश थी।

20 अक्टूबर 2023 को मास्क पहने अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मलिक दाऊद उर्फ खान मलिक दाऊद उर्फ दाऊद मलिक की हत्या कर दी है। मलिक दाऊद मुसाकी गांव का रहने वाला था । पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी तो उस वक्त दाऊद मलिक की वहां पर उपस्थिति बताई गई थी लेकिन वह एयरस्ट्राइक के दौरान बाल-बाल बच गया था।

11 अक्टूबर 2023 को पठानकोट हमले के मास्टमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट की मस्जिद में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लतीफ एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। 2 जनवरी, 2016 को जैश के आतंकियों ने पठानकोट में एयरबेस पर हमला कर दिया था। इसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। 36 घंटे एनकाउंटर और तीन दिन तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चला था। शाहिद लतीफ आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (खीट) का एक प्रमुख सदस्य था। उसने ही चारों आतंकवादियों को पठानकोट भेजा था। लतीफ 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा करने में भी शामिल था। लतीफ को नवंबर 1994 में भारत में गिरफ्तार किया गया था, और मुकदमा चलाया गया था। कांग्रेस सरकार ने भारत में सजा पूरी होने के बाद 2010 में उसे वाघा के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया था। लतीफ 2010 में अपनी रिहाई के बाद पाकिस्तान में जिहादी फैक्ट्री में वापस चला गया था।

10 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तानी आतंकवादी और आ-ईएसआई एजेंट मुल्ला बाहौर उर्फ होर्मुज उर्फ महद उर्फ अब्दुल लतीफ को कुछ अज्ञात लोगों ने बलूचिस्तान के केच इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी। मुल्ला बाहौर ने ही ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा किया था और फिर उसे आईएसआई के हवाले किया था। कुलभूषण जाधव बिजनेस करते थे और भारतीय नौसेना से रिटायर थे। इस वक्त वह पाकिस्तान की जेल में हैं। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दस्तक दी थी। वहां से कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाई गई है।

30 सितंबर 2023 को 26/11 मुंबई टेरर अटैक के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी हाफिज सईद के सबसे करीबी माने जाने वाले मुफ्ती कैसर फारूक की भी कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। कैसर फारूक लश्कर के संस्थापक सदस्यों में से एक था और हाफिज सईद का बेहद करीबी सहयोगी था। 30 वर्षीय कैसर फारूक को 30 सितंबर 2023 को समानाबाद इलाके में एक धार्मिक संस्थान के पास गोली मारी गई।

ये तमाम हत्याए इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि भारत के खिलाफ जेहाद के लिए पाकिस्तान ने जिन दानवों को पाल पोसकर बडा किया आज उन्होंने अपने अत्याचार से वहां के स्थानीय लोगों को भी इतना अधिक पीडित किया कि वहां बने स्थानीय दुश्मन ही अब उन्हें नेस्तोंनाबूद कर रहे हैं।

पिछले नौ साल से सेना के जवानों संग दीवाली मनाते रहे हैं पीएम मोदी

प्रणव गोस्वामी @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2014 में सत्ता संभालने के बाद से ही अलग-अलग जगहों पर देश की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा को टूटने नहीं दिया है। इस साल सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के लेप्चा पहुंचे। उन्होंने भारत के सीमावर्ती इलाके पर स्थित देश के आखिरी गांव, जिसे अब पहला गांव माना गया है, में तैनात जवानों के साथ देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेना की जैकेट और टोपी में नजर आए। उन्होंने बहादुर जवानों के जज्बे को सलाम किया और उनके बलिदान की परंपरा को नमन किया। उन्होंने कहा कि जहां जवान तैनात हैं वह जगह मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। आप जहां भी हैं, मेरा त्योहार वहीं है। ऐसा शायद 30-35 वर्षों से चल रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के बहादुर जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्सव वहीं होता है जहां परिवार रहता है। उन्होंने सीमा की सुरक्षा के लिए त्योहार के दिन अपने परिवार से दूर रहने की स्थिति को कर्तव्यों के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा बताया। 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार मानने की भावना सुरक्षाकर्मियों के उद्देश्यों को सार्थकता प्रदान करती है। देश इसके लिए आपका आभारी और ऋणी है। इसीलिए हर घर में आपकी सुरक्षा के लिए एक 'दीया' जलाया जाता है।

इससे पहले 2022 में पीएम मोदी ने कारगिल में जवानों के साथ मनाई दिवाली मनाई थी। उससे पहले साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में दिवाली मनाई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2020 में सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने

के लिए राजस्थान के जैसलमेर स्थित लोंगेवाला चौकी पहुंचे थे। 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और क्ळइढ के जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2017 की दीपावली जम्मू-कश्मीर के गुरेज में जवानों के बीच मनाई। 2016 में दीपावली मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर जा पहुंचे। वर्ष 2015 में दीपावली के दिन प्रधानमंत्री अमृतसर में खासा स्थित डोगराई युद्ध स्मारक गए और पुष्पांजलि अर्पित की। यह स्थान सबसे कठिन युद्धस्थल के रूप में जाना जाता है।

भारतीय सैनिकों ने 22 सितंबर, 1965 के युद्ध में यहीं विजय प्राप्त की थी। अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने इस परंपरा की शुरूआत करते हुए, देश के सबसे कठिन सैन्य क्षेत्र, सियाचिन में सैनिकों के संग दीपावली मनाई थी।

क्या आखिरी दौर में चल रहा है इसराइल-हमास युद्ध

इसराइली आर्मी ने हमास की संसद पर कब्जा कर अपना झंडा लहराया

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजा। इजरायल हमास युद्ध का मंगलवार को 39वां दिन थौ। लेकिन गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच अब भी लड़ाई जारी है। युद्ध की वजह से गाजा में अब तक 23 लाख लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है।

7 अक्टूबर से चल रही इस जंग में 11,000 से अधिक फलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इजरायल ने कहा कि सेना ने गाजा सिटी को चारों ओर से घेर रखा है। वहीं, इजरायल के एक सैनिक ने यह दावा किया है कि सेना ने हमास की 'संसद' पर कब्जा कर लिया है।

सोशल मीडिया पर इजरायली सेना ने एक फोटो साझा किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड गाजा में मौजूद हमास के संसद भवन के अंदर मौजूद हैं और वे अपने देश का झंडा लहरा रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इजरायली सैनिक संसद की स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हैं।

फलस्तीनी विधान परिषद भवन 2007 से हमास के नियंत्रण में था, जिसे अब इजरायली बलों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है।

एफपी की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, हृहमास के जिन आतंकियों ने गाजा पट्टी पर 16 सालों से नियंत्रण किया अब वो अपना नियंत्रण खो चुके हैं। योव गैलेंट ने आगे कहा,हमास के लड़ाके दक्षिण गाजा की ओर भाग रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने आगे बताया, 'हमास के ठिकानों को फलस्तीनी नागरिक लूट रहे हैं। गाजा के नागरिकों में सरकार (हमास की सरकार) को लेकर कोई आस्था नहीं रह गई है।'

इजरायल ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक हमास के कब्जे में मौजूद सभी इजरायली नागरिकों को हम रिहा नहीं कर लेते तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। इजरायली सेना आर-पार की लड़ाई लड़ रही है। कुछ दिनों पहले इजरायल ने कहा था कि गाजा को दो हिस्सों (उत्तर और दक्षिण) गाजा में बांट दिया गया है। गाजा सरकार द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार, मृतकों में 4,630 बच्चे और 3,130 महिलाएं थीं, जबकि अन्य 29,000 लोग घायल हुए थे। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी गाजा की सड़कों पर दर्जनों शव पड़े हुए हैं। यहां सबसे भीषण लड़ाई चल रही है। जब उन्होंने उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो, एम्बुलेंस इजरायली गोलीबारी की चपेट में आ रही हैं।

हमास के खात्मे तक यह युद्ध जारी रहेगा: बेंजामिन नेतन्याहू

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि हमास के खात्मे तक यह युद्ध जारी रहेगा। यह केवल एक ह्यऑपरेशनह्न या ह्यराउंडह्न नहीं है, बल्कि आतंकवादी समूह द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने का एक निरंतर प्रयास है। अगर हम इन्हें खत्म नहीं करते हैं, तो यह वापस आएगा।

युद्ध की भेंट चढ़ते मासूम बच्चे

उत्तरी गाजा में मौजूद अल-शिफा अस्पताल में बिजली कटौती और चिकित्सा आपूर्ति की कमी के कारण छह नवजात शिशुओं सहित पंद्रह मरीजों की मौत हो गई है। बता दें कि इजरायली सेना ने सोमवार को जानकारी दी थी कि उसने गाजा के अल-कुद्स अस्पताल में नागरिकों के बीच हमास लड़ाकों के एक समूह को निशाना बनाया था।

संपादकीय

ये कयामत नहीं तो क्या है

कुछ रोज पहले थोड़ी बारिश से दिल्ली के हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन दो दिन पहले की बात है। गाजियाबाद में तीन लोगों की सांस की तकलीफ से मौत हो गई। इनको बुखार और दूसरी सामान्य बीमारियां भी थीं, लेकिन उनकी हालत तब ज्यादा खराब हुई जब एनसीआर का एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 400 से ऊपर था। इन मौतों के कारण में कई कारण सामने आ सकते हैं। फिर भी इस बात से किसी एक डॉक्टर या पल्मोनरी या छाती रोग एक्सपर्ट को इनकार नहीं होगा कि दमा और सांस के रोगियों के लिए लिए ही नहीं, आम लोगों के लिए भी नैशनल कैपिटल रीजन की ऐसी आबोहवा एक धीमा जहर है।

छह साल पहले की बात है। यूनाइटेड नेशन की 2017 में हुई बॉन क्लाइमेट समिट में जाना हुआ। वहां देखा कि एक वीवीआईपी जेंटलमैन जोर-जोर से रो रहे हैं और मीडिया उन्हें घेरे है। पता चला कि वह एलायंस ऑफ स्मॉल आईलैंड स्टेट्स ओएसिस से जुड़े एक देश के पर्यावरण मंत्री हैं। ओएसिस मतलब छोटे-छोटे समुद्र द्वपीय देशों का समूह। आप इसे आसानी से समझने के लिए मालदीव जैसे देशों का समूह कह सकते हैं। उनकी फिक्र इस बात को लेकर थी कि यूरोप अमेरिका जैसे विकसित और भारत-चीन और दूसरे विकासशील देशों के समूह हर कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अपना अपना पक्ष लेकर आपस में लड़ते हैं। उन्हें बिलकुल फिक्र नहीं कि उनके देश जैसे छोटे-छोटे आइलैंड मुल्क कुछ ही दिनों में डूब जाएंगे।

अब वापस आते हैं दिल्ली और उत्तर भारत के हाल पर। स्कूल बंद हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि कोर्स कैसे पूरा होगा, ऑड-ईवन गाड़ियों को सड़क पर निकलने देने को लेकर बहस है और अस्पतालों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती हा रही है। इतनी दुश्वारियों के बावजूद यहां भी हाल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जैसा है। नीले आसमान को तरसते दिल्ली-एनसीआर को मिलजुल कर बचाने के बजाए केन्द्र और राज्य सरकारें यहां एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट चेतावनी दे रहा है कि अगर उनका बुलडोजर चला तो फिर रुकेगा नहीं और किसान खेतों में आग रोकने आए अधिकारियों को घेरकर उनसे ही पराली जलवा रहे हैं।

साफ नजर आ रहा है कि हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। हालात यहां तक है कि दिल्ली का मिडल क्लास एयर प्यूरीफायर और ज्यादा बड़ी कोठियों वाले ऑक्सिजन सिलिंडर और मास्क के साथ सोना शुरू कर चुके हैं। फिर सवाल है कि इस जानलेवा माहौल को ठीक कैसे किया जाए। लंदन शहर का इतिहास देखें तो 1850 के आसपास ब्रिटेन की राजधानी का भी ऐसा ही हाल था। अजीब सी बदबू पूरे शहर में फैली रहती थी। टेम्स नदी का हाल यमुना जैसा था, जिसमें सीवर, लाशें और कचरे से बदबू आती रहती थी। औद्योगिक क्रांति के कारण हजारों अप्रवासी मजदूर वहां अनियोजित तरीकों से रहते थे। तब वहां के मेयर और प्रशासन ने लंदन को साफ करने का बीड़ा उठाया। बाहर से आए लोगों को ठीक से बसाने के लिए कॉलोनियां बनाई गईं, अच्छा सीवर सिस्टम बनाया और कारखानों की गैस से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया गया। टेम्स जो मुर्दा नदी घोषित थी, उसे साफ करके जिंदा किया गया। आज के दिल्ली-एनसीआर और यमुना को देखिए तो हालात 1850 वाले लंदन जैसे ही हैं। देखा जाना चाहिए कि वहां क्या किया गया था? आज के वक्त के हिसाब से उन कोशिशों को कैसे यहां किया जा सकता है। कैसे यहां भी दिवाली पर नीला आसमान नजर आए और हवा सांस देने के लिए हो, न कि लेने के लिए।

वैश्विक स्तर पर लोगों को गुमराह करती सोशल मीडिया कंपनियां

अमेरिका में इन दिनों बिग टेक कंपनियों, विशेषकर सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर खासी चिंता है। हाल ही में वहां दर्जनों राज्यों ने इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा पर मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें आरोप लगाया है कि कंपनी के सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स से छोटे बच्चों और किशोरों को नशे की लत के लिए उकसाया गया है। इसने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाला है। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सहित 33 अमेरिकी राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने कहा है कि मेटा ने अपने प्लैटफॉर्म्स के खतरों के बारे में जनता को बार-बार गुमराह किया।

अमेरिका में दर्ज मुकदमों में कहा गया है कि मेटा ने युवाओं और किशोरों को लुभाने, ईगेज करने और आकर्षित करने के लिए शक्तिशाली और अभूतपूर्व तकनीकों का उपयोग किया है। मुकदमों में यह भी कहा गया है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक यंग यूजर्स में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नामक मानसिक बीमारी को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिया में व्यक्ति अपनी किसी शारीरिक खामी को लेकर इतना चिंतित रहता है कि वह समाज से खुद को काटने लगता है। हांलाकि मेटा ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि हम किशोरों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए पहले ही 30 से अधिक उपकरण पेश कर चुके हैं। इसके पहले, अमेरिकी राज्य यूटा ने मार्च में एक ऐसे कानून की घोषणा की जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सोशल मीडिया साइट्स का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। यह कानून मार्च 2024 से लागू होना है। माना जा रहा है कि इससे सोशल मीडिया की बढ़ती लत और ऑनलाइन क्राइम जैसे जोखिमों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। इन मुकदमों में जो बातें हैं, कुछ ऐसे ही आरोप दो साल पहले मेटा की पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस हाउगेन ने भी लगाए थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर किए गए एक आंतरिक अध्ययन का खुलासा करते हुए बताया था कि ऐप का उपयोग करने वाली कई युवा लड़कियां डिप्रेशन और बॉडी शेमिंग से पीड़ित थीं। इसी बीच यह सूचना भी सार्वजनिक हुई कि मेटा ने तीसरी तिमाही में उम्मीद से ज्यादा मुनाफा कमाया है। पिछली तिमाही (जुलाई, अगस्त, सितंबर) में मेटा के डेली एक्टिव यूजर (डीएपी) की संख्या में 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, और ऐड इंप्रेशंस में 31 फीसदी की वृद्धि रेकॉर्ड की गई। सोचने वाली बात है कि क्या इन दोनों खबरों में कोई संबंध है। क्या सचमुच युवाओं में इन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्मों की लत से टेक दिग्गज के मुनाफे में इजाफा हो रहा है?

सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता कोई नई बात नहीं है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डेटा के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली 30 फीसदी अमेरिकी लड़कियों ने आत्महत्या करने पर गंभीर रूप से विचार किया। अप्रैल 2021 में प्रकाशित प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के मुताबिक 18-29 साल के अधिकांश युवाओं ने कहा कि वे इंस्टाग्राम (71 फीसदी) या स्नैपचैट (65 प्रतिशत) का उपयोग करते हैं। इस आयु वर्ग के आधे उत्तरदाताओं ने कहा कि वे टिक टॉक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दूसरे शोध में पाया गया है कि सोशल मीडिया का उपयोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन से जुड़ा है। अमेरिका की चिंता जायज है। लेकिन सवाल है कि अमेरिका से ज्यादा सोशल मीडिया उपयोगकर्ता वाले देश भारत में इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? दुनिया की लगभग 60 फीसदी जनसंख्या सोशल मीडिया यूजर है और ये लोग प्रतिदिन लगभग 2 घंटा 27 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। भारत का डेली एवरेज इस ग्लोबल डेली एवरेज से कहीं अधिक है। साफ है कि भारत में सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ज्यादा चिंता होनी चाहिए। लेकिन सच यह है कि मेटा और गूगल जैसी कंपनियों ने भारतीय डेटा संरक्षण अधिनियम का पालन करने के लिए भी 12-18 महीने का समय मांगा है।

विशेष खबर हिन्दी साप्ताहिक

REGISTERED & ADMINISTRATIVE OFFICE:
ए-288 नेहरू नगर द्वितीय, गाजियाबाद, उ0प्र0
(Mob.) 9711345310

संपादकः विनीतकांत पाराशर
समाचार संपादक : सुनील कुमार वर्मा
ले-आउट डिजाइनः रजनी वर्मा

समाचार, लेख व विज्ञापन के लिए संपर्क करें
e-mail: visheshkhabarvk@gmail.com,
visheshkhabar.tv@gmail.com
contact: (Mob.) 9711345310

@ विशेष खबर में छपे सभी लेख व खबरों पर हुए वाद विवाद को सुलझाने के लिए न्याय क्षेत्र गाजियाबाद में मान्य होगा।

क्या है राजनीतिक दलों के चुनावी गारंटियों के लॉलीपॉप का अर्थशास्त्र ?

विनीत कांत पाराशर
प्रंधान संपादक

इन दिनों राजनीति में सत्ता में आने के लिए कुछ फॉमूले इस तरह हिट हो रहे हैं कि हर चुनाव में राजनीतिक दल सफलता हासिल करने के लिए इन्हीं फॉमूलों का इस्तेमाल करने लगे हैं। कांग्रेस ने हिमाचल में चुनावी गारंटियों के जिस जिस लॉलीपॉप फॉमूले का इस्तेमाल किया वह इस कदर हिट हुआ कि अब वह हर राज्य में चुनाव के दौरान इसी फॉमूले का इस्तेमाल कर रही हैं, हांलाकि भाजपा भी इसी फॉमूले का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इन गारंटियों को पूरा करने का अर्थशास्त्र आखिर क्या है?

कुछ साल पहले तक मुंबइया सिनेमा का प्रमुख आधार फॉम्युर्ला होता था। किसी खास फॉम्युर्ले पर फिल्म हिट हुई नहीं कि हर छोटा-बड़ा निमार्ता उसी फॉम्युर्ले को दोहराने लगता था। राजनीति भी कुछ उसी अंदाज में चलती है। किसी पार्टी विशेष का कोई फॉम्युर्ला अगर एक बार सत्ता की सीढ़ी बन गया तो पार्टी चुनावी अभियान में उसे बार-बार लागू करने लगती है। गारंटी स्कीम कांग्रेस का ऐसा ही फॉम्युर्ला है, जिसकी बुनियाद पर पार्टी ने कर्नाटक में जीत हासिल की। जीत की वजह बने इस फॉम्युर्ले को अब पार्टी दूसरे राज्यों में भी आजमा रही है। चाहे छत्तीसगढ़ की आठ गारंटी हों या राजस्थान की सात गारंटी या फिर मध्य प्रदेश के ग्यारह वचन, सब कर्नाटक फॉम्युर्ले का ही विस्तार हैं।

कांग्रेस इन राज्यों की जनता से जो वादे कर रही हैं, उन पर मोटी रकम खर्च होने वाली है। सवाल यह है कि इन गारंटियों को पूरा करने के लिए कांग्रेस की सरकारें धन कहां से लाएंगी।

कर्नाटक के लिए जब कांग्रेस ने पांच गारंटी का वादा किया, तब अनुमान लगाया गया था कि उस पर 62 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह रकम राज्य के कुल बजट का करीब 20 फीसदी होती। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि इस पर राज्य के कुल बजट का करीब पंद्रह फीसदी ही खर्च होगा। हिमाचल प्रदेश में पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने और महिलाओं को मासिक सहायता भत्ता देने का वादा किया था। वहां भी सरकार आर्थिक बोझ से जूझने लगी है। दरअसल, गारंटियों पर राज्यों के भारी-भरकम खर्च बढ़ने के बाद उनका आर्थिक ढांचा गड़बड़ा रहा है। इस पर आंकड़ों की रोशनी में ठीक से गौर करने की जरूरत है।

कर्नाटक सरकार के वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार उसका राजकोषीय घाटा 66 हजार 646 करोड़ रुपया हो

दृष्टिकोण

गया है। राज्य पर पहले से ही करीब पांच लाख करोड़ का कर्ज है।

हिमाचल प्रदेश पर करीब 75 हजार करोड़ का कर्ज है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने साल 2023-24 के लिए जो बजट पेश किया, उसके अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा नौ हजार नौ करोड़ होने का अनुमान है।

अब जरा उन राज्यों पर भी नजर डालते हैं, जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस गारंटियों की बरसात कर रही है।

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश ने 2019 से 2022 के बीच 89 हजार 444 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। राजस्थान ने इसी अवधि में एक लाख 47 हजार 600 करोड़ रुपये का ऋण लिया है। छत्तीसगढ़ ने 28 हजार 680 करोड़ और तेलंगाना ने दो लाख 37 हजार 402 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। यह तो हुई सिर्फ एक साल की बात। इन राज्यों पर मार्च, 2023 तक के कुल कर्ज भी ध्यान दिया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के अनुसार इस अवधि तक मध्य प्रदेश पर कुल 3 लाख 78 हजार 617 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया था। वहीं, राजस्थान पर 5 लाख 37 हजार 13 करोड़ रुपये और तेलंगाना पर 3 लाख 66 हजार 606 करोड़ रुपये का कुल कर्ज था।

कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों पर कुल कितना खर्च आएगा, इसका अभी अर्थशास्त्रियों ने समेकित अनुमान नहीं लगाया है। लेकिन यह तय है कि यह रकम लाखों करोड़ रुपये होगी। इन गारंटियों पर खर्च होने वाली रकम कहां से आएगी? इसका कोई रोड मैप कांग्रेस के पास नहीं है। अगर होता तो कर्नाटक या हिमाचल की सरकारों की ओर से दिख गया होता। कुछ ऐसी ही गारंटी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी दी। सचाई यह है कि जिन राज्यों में भी गारंटियां दी गईं और गारंटी देने वाली पार्टी की सरकार आई, उनकी आर्थिक स्थिति डांवाडोल है।

गारंटी का असर यह हो रहा है कि राज्यों में नियमित विकास कार्य रुक रहे हैं। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में पानी की कमी है, लेकिन पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। गारंटी से फायदा उठा रही जनता को इससे ज्यादा लेना-देना नहीं रहता। जब बदहाली होती है तो राज्य सरकारें केंद्र को जिम्मेदार ठहराने लगती हैं। जैसे कर्नाटक सरकार भी जल समस्या के लिए केंद्र को ठहरा रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार भी ऐसा ही करती रही है।

वैसे, गारंटी तो केंद्र और बीजेपी की सरकारें भी दे रही हैं। केंद्र सरकार 84 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। मध्य प्रदेश की सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत हजार रुपये महीना महिलाओं को दे ही रही है। लेकिन इखढ कह सकती है कि उसे अपनी राजनीतिक अस्मिता के लिए कांग्रेस की गारंटी योजना का जवाब देना ही पड़ेगा।

बहरहाल, प्रियंका गांधी हों या राहुल गांधी, उन्हें भरोसा है कि उनकी गारंटी योजना उनकी सत्ता के सूखे को खत्म करेगी। वैसे भी कांग्रेस इन दिनों वाम मार्गी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उस सोच में राजकोष पर पड़ रहे दबाव के बजाय जनता को राहत और उसका पॉप्युलर समर्थन ज्यादा मायने रखता है। राहुल गांधी का जाति जनगणना की मांग करना भी इसी पॉप्युलर पॉलिटिक्स का विस्तार है। कांग्रेस गारंटी और जाति के सहारे देश की राजनीति को अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है। देखना यह है कि बीजेपी देश की सबसे पुरानी पार्टी के नव वाम चिंतन का कितना और कैसा जवाब दे पाती है।

नज़रिया

केशव चावला, वरिष्ठ पत्रकार

जनता को मिलनी ही चाहिए राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी

चुनावी बॉन्ड की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके तहत व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं, जिसे राजनीतिक दल बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। लेकिन, इसका स्याह पक्ष यह है कि यह गुप्त होता है। चुनावी या कहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने आज जो दलीलें दी हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो गौर किया ही है, लेकिन ये दलीलें आम लोगों के भी गौर करने लायक हैं।

आखिर यह बॉन्ड आम आदमी के अधिकारों का ही तो अतिक्रमण करता है? वह लोकतंत्र, जहां जनता को मालिक बताया जाता है, वहां जनता को यह जानने का अधिकार न होना कि किसने, किस राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया, उसके अधिकारों पर प्रहार ही तो है? वकील प्रशांत भूषण ने भी आज कोर्ट में यही कहा कि यह आम लोगों के चीजों को जानने के अधिकार का हनन है। हालत यह है कि सिर्फ सरकार को पता होता है कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया है। यहां तक कि चुनाव आयोग तक को पता नहीं होता। क्या यह ठीक है?

इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे वाकई मंशा क्या थी?

वाकई यह कितनी बड़ी बात है कि वे नेता, जो देश की जनता को अपना मालिक बताते हैं, वे उसे नहीं बताना चाहते हैं कि उनकी पार्टियों को कहां से कितना चंदा मिला है? वैसे भी यह सिर्फ चाहने, न चाहने की बात नहीं है। बाकायदा इसके लिए कानून बनाया गया कि चाहकर भी इस बारे में कोई सवाल न कर पाए। इसलिए तो आज यह जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून लागू किया कि अब किसने, किसे, कितना चंदा दिया, यह गुप्त रखा जाएगा। भाजपा वाली केंद्र सरकार का कहना था कि इससे चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी। लेकिन, क्या यह दावा सच था? क्या वाकई ऐसा हुआ? सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण की इस दलील से भी आप समझ सकते हैं कि हालात क्या है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई कंपनियां ऐसी हैं, जिन्होंने डोनेशन दिया और एवज में उन्हें माइनिंग का ठेका मिला। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में पार्टियों को मिले चंदे का भी ब्यौरा कोर्ट में पेश किया है।

भाजपा को ही सबसे अधिक चंदा क्यों मिला?

गौर करें तो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, जो सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे के आधे से भी ज्यादा है। बीजेपी को कुल 5271 करोड़ रुपये मिले हैं। कांग्रेस को भी 952 करोड़ रुपये मिले हैं। ट-ीएमसी को 767 करोड़ और बीजेडी को 622 करोड़ रुपये मिले हैं। लेकिन, हमें बस इतना ही पता चल

सकता है। यह नहीं कि किसने, कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। फिर यह भी बताने की जरूरत क्या है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला? सिर्फ यह जानकर आम आदमी क्या कर लेगा? या कोई जांच एजेंसी भी क्या कर लेगी?

लेकिन, कानून बनाकर आम जनता से भले ही यह जानने का अधिकार छीन लिया जाए कि किस पार्टी को कितना चंदा किसने दिया, क्या उसकी सोचने-समझने की क्षमता भी कुंद कर दी जाएगी? क्या इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं समझ सकता कि केंद्र या फिर राज्यों में, जो पार्टियां सत्ता में हैं, उन्हें ही क्यों अधिक चंदा मिल रहा? यह तो रिश्वत का एक कानूनी तरीका भी हो सकता है ना कि कोई सत्तासीन पार्टी को चंदा दे और फिर उसके बदले में अपना काम करा ले? यही तो प्रशांत भूषण ने भी कहा है।

किसने, किसे चंदा दिया, पता चल जाए तो क्या होगा?

अब आते हैं इस बात पर कि किसने, किसे, कितना चंदा दिया, यदि यह सार्वजनिक हो जाए तो इसके खतरे क्या हो सकते हैं? आखिर इन्हीं बातों का हवाला देकर तो यह कानून लाया गया हो सकता है? जैसा कि आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने भी कहा कि यदि कोई डोनर किसी राज्य में बिजनेस चलाता है और अगर उसका नाम सामने आता है कि उसने किस पार्टी को डोनेशन दिया है तो यह उसके प्रतिद्वंद्वी पार्टी को भी पता चलेगा। रउ की इन बातों से पता चलता है कि आशंका है कि यदि प्रतिद्वंद्वी पार्टी को पता चले तो वह उस बिजनेसमैन को परेशान कर सकता है।

लेकिन, क्या इस आशंका से भी लोकतंत्र में आम लोगों को पार्टियों को चंदा के रूप में मिलने वाले धन के बारे में बताने से इनकार कर देना ठीक है, जहां कि वह मालिक बताई जाती है और नेता खुद को सेवक या चौकीदार कहते हैं? फिर तो कोई पार्टी बा-ॅन्ड के जरिए रिश्वत लेकर कॉरपोरेट के काम करती रहेगी और अनजान जनता उसे ईमानदार समझते हुए उसे ही सरकार के रूप में चुनती रहेगी? खतरा तो यह भी है ना? क्या इस खतरे को नजरअंदाज किया जाना चाहिए?

रायसीना की जुगलबंदी

सुनील वर्मा

भाजपा में वंशवाद का मुद्दा

बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र येदियुरप्पा को अपनी कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष बनाकर, बीजेपी ने पार्टी नेताओं के एक वर्ग द्वारा उठाए जा रहे भाई-भतीजावाद के मुद्दे को समाप्त कर दिया है। माना जा रहा है कि यह मुद्दा भविष्य में चुनावी भाषणों में तो कुछ कहा जा सकता है, लेकिन संगठन में नियुक्तियों के लिए अब यह कोई मुद्दा नहीं है। राज्य इकाई के कई नेता इस नियुक्ति के विरोध में थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इसे सुरक्षित तरीके से खेलने का फैसला किया है।

लापता पायलट और कांग्रेस का संकट

यह दावा करने के बावजूद कि राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व के भीतर सब कुछ ठीक है, जमीन पर चीजें अलग दिख रही हैं। जयपुर में पार्टी मुख्यालय पर लगे पोस्टरों से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तस्वीरें गायब हैं. इन पोस्टरों के सामने आने के बाद से ही राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और यह राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक बार फिर इस बात पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या पार्टी आलाकमान वाकई कांग्रेस में नेतृत्व संकट को हल करने में सक्षम है।

आरएलडी से बढ़ती कांग्रेस की मुश्किलें... बस एक सीट

राजस्थान में कांग्रेस से चार-पांच सीटों की उम्मीद कर रही राष्ट्रीय लोकदल को केवल एक सीट आवंटित की गई है। आरएलडी नेताओं का मानना है कि इस अप्रत्याशित व्यवहार पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भले ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरह खुलकर कांग्रेस के खिलाफ नहीं उतरे हों, लेकिन उन्होंने इस आवंटन पर ध्यान दिया है। इस कदम का असर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर दिखने की संभावना है।

वाह... रेलवे !

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर वंदे भारत एक्सप्रेस के केरल के हरे-भरे वेल्लायिल रेलवे स्टेशन से गुजरने की एक पोस्ट साझा की। दो ट्रेनों की कोलाज छवि ने कई नेटिजन्स को मंत्री की एक्स पोस्ट पर टिप्पणी करने के लिए आकर्षित किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वैष्णव वर्तमान सोशल मीडिया रुझानों पर भी अच्छी तरह से नजर रखते हैं। उन्होंने न केवल तस्वीरें पोस्ट कीं, बल्कि एक कैप्शन भी लिखा, 'बिल्कुल वाह जैसा लग रहा है'। यह वाक्यांश हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध हो गया।

सपा व बसपा के भरोसे भाजपा की उम्मीद

वैसे तो मध्य प्रदेश में 18 साल की सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर जाती दिख रही है। लेकिन अपने जबरदस्त इलेक्शन मैनेजमेंट के बाद भाजपा चाहती है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के विपक्षी उम्मीदवार आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करें। दरअसल अब चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर की भविष्यवाणी की जा रही है, पार्टी को उम्मीद है कि इन दोनों पार्टियों की 10-10 सीटों की जीत भी उसकी वापसी सुनिश्चित कर सकती हैं। दरअसल ये दोनों पार्टियां जितनी मजबूती से चुनावी लडेगीं उतना ही कांग्रेस को नुकसान होगा और भाजपा का फायदा। लेकिन प्रदेश में कोई बडा जनाधार न होंने के बावजूद

सपा ने एक ही गठबंधन में होंने के बावजूद जितनी बडी तादाद में एमपी में उम्मीदवार खड़े किए उसे भी भाजपा का दबाव और रणनीति ही बताया जा रहा है।

राहुल और वरुण गांधी का केदानाथ में मंगल मिलन

गांधी परिवार के दो वंशज, राहुल और वरुण, राजनीतिक स्पेक्ट्रम के विपरीत पक्षों पर खड़े हैं, ऐसे में दोनों जब केदारनाथ में मिले तो इस 'मौका' मुलाकात से 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलकों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पिछले कुछ महीनों से वरुण गांधी बीजेपी के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हो रहे हैं। पीलीभीत से सांसद वरूण गांधी भगवा इकाई में नाखुश हैं। वे जब तब पार्टी की नीतियों और खास मुद्दों पर उंगलियां भी उठाते रहते हैं।

चर्चा तो ये भी है कि आम चुनाव से पहले वे पार्टी के बाहर विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में भैय्या राहुल ये उनकी मुलाकात जब केदारनाथ में हुई तो कयासबाजी और राजनीतिक अटकलबाजियां तो शुरू होंगी ही। क्योंकि राजनीतिक पंडित तो पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में राहुल और वरूण भैय्या के साथ बहन प्रिंयका का त्रिकोण एक साथ खड़ा दिखाई देगा!

महापुरूषों के विचार

स्वामी विवेकानंद

एक अच्छी किताब सौ अच्छे दोस्तों के बराबर होती हैं, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता हैं।

social media fact chek of the week

गाय का मांस खाने का दिग्विजय का वीडियों दो साल पुराना

मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर कई फर्जी और भ्रामक पोस्ट वायरल हो रही हैं। अब एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक वीडि-यो वायरल हो रहा है। इसमें दिग्विजय सिंह को कहते हुए सुना जा सकता है कि गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं है। इसे शेयर कर कुछ यूजर्स कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। विशेष खबर की जांच में पता चला कि दिग्विजय सिंह का वायरल वीडियो करीब दो साल पुराना है। दिसंबर 2021 में उन्होंने सा-वरकर की किताब के अंश का हवाला देकर कहा था कि गौमांस खाने में कोई खराबी नहीं है।

ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस भाजपा में रार

राहुल गांधी का वार V/S पीएम मोदी का पलटवार

मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गाधी ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि मोदी कहते हैं देश में सिर्फ एक ही जाति है गरीब की, लेकिन जाति जनगणना पर सवाल करो तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। जबकि हर इंसान जानना चाहता है और मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि देश में किस जाति की कितनी संख्या है उन्हें सरकार की तरह से जो लाभ मिलना चाहिए वो उचित संख्या में मिल रहा है या नहीं।

राहुल के वार पर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पलटवार करते हुए कहा, 'आपको कांग्रेस की मानसिकता को पहचानना होगा। यह वही कांग्रेस है जिसने पंचायत से संसद तक सरकारें चलाई, लोगों ने उन्हें सरकार चलाने का अवसर दिया, लेकिन ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दिया। यह वही कांग्रेस है जिसने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया और मेडिकल कॉलेज में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया।'

शख्सियत

नब्बे के दशक में भाजपाई राजनीति में पर्दे के आगे और पीछे दोनों जगह होते थे प्रमोद महाजन

भाजपा के नेता रहे प्रमोद महाजन की आज यानी की 30 अक्तूबर को बर्थ एनिवर्सरी है। प्रमोद महाजन एक जबरदस्त संभावनाओं वाले नेता थे। 90 के दशक में जब भाजपा की राजनीति शिखर पर चढ़ने लगी तो प्रमोद महाजन इस सियासत के सबसे असरदार चेहरे हुआ करते थे। उनको बीजेपी की दूसरी पीढ़ी का चाणक्य भी कहा जाता था। प्रमोद महाजन ऐसी शख्सियत थे, जो पर्दे के पीछे भी होते थे और पर्दे के सामने भी। जनता के साथ खास तरीके से वह मुस्कुराते चेहरे के साथ रूबरू होते थे।

जन्म और शिक्षा

प्रमोद महाजन का जन्म तेलंगाना में 30 अक्तूबर 1949 को हुआ था। वह छात्र जीवन से ही संघ से जुड़ गए थे। संघ का इनके जीवन पर विशेष प्रभाव रहा। प्रमोद महाजन ने ने पुणे के रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म से पत्रकारिता की थी। फिर वह आरएसएस के मराठी अखबार ह्यतरुण भारतह्न के उप संपादक बन गए। जिसके बाद साल 1974 में प्रमोद महाजन को संघ प्रचारक

बनाया गया। वहीं इमरजेंसी के समय उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विरोध का मोर्चा भी संभाला था।

बीजेपी के संकटमोटक

बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कई मामलों में प्रमोद महाजन ने संकटमोचक की भूमिका निभाई। वह बैकरूम स्ट्रैटजी में काफी ज्यादा माहिर थे। वहीं 90 के दशक के आखिर तक अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद बीजेपी की राजनीति में जो दो असरदार चेहरे नजर आने लगे थे। उनमें से एक प्रमोद महाजन थे। उन्हें लोग होमवर्क में परफेक्ट, चतुर और जनता के करीब रहने वाले मजबूत नेता के तौर पर जानने लगे थे। प्रमोद महाजन का असर ना सिर्फ पार्टी संगठन बल्कि सरकार के साथ संघ पर भी नजर आता था।

बखूबी तैयार किया जनाधार

हांलाकि यह बात भी बिलकुल सच है कि 90 के दशक में जब वह भाजपा के सेकेंड लाइन लीडरशिप के तौर पर उभर रहे थे। तो प्रमोद महाजन का जनाधार नहीं था। लेकिन फिर उन्होंने इस जनाधार को बखूबी तैयार किया। 90 का दशक ऐसा दशक भी था, जब इस देश में बाजार के जरिए धन का प्रवाह बढ़ा। इस दौरान तकनीक का नया युग भी शुरू हो रहा था। वहीं प्रमोद महाजन को तकनीक में माहिर माना जाता था।

मोबाइल क्रांति में भी योगदान

भारत में यह वही दौर था जब लैंडलाइन फोन की जगह मोबाइल फोन और उनके नेटवर्क का जाल फैल रहा था। उस दौरान केंद्र सरकार में प्रमोद महाजन संचार मंत्री थे। लेकिन वह आरोपों से भी बचे नहीं रहे। हांलाकि प्राइवेट कंपनियों को मोबाइल नेटवर्क के आवंटन और तकनीक को देश में लाने में प्रमोद महाजन की भूमिका अहम रही।

मेहनत से कमाई राजनीति

प्रमोद महाजन ने अपनी मेहनत से राजनीति कमाई थी। उन्हें राजनीति ना तो विरासत में मिली और ना ही किस्मत से। इसे उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से हासिल किया था। बीजेपी में जहां अटलबिहारी वाजपेयी को वाकचातुर्य, लालकृष्ण आडवाणी को सांगठनिक गुणों में संपन्न कहा जाता था। तो वहीं प्रमोद महाजन को सियासी कुटिलता और समझबूझ में अपने राजनीतिक गुरुओं से भी आगे माना जाता था। जिसके कारण वह अपनी पार्टी में भी ईर्ष्या के पात्र थे। उस दौर में प्रमोद महाजन की क्षमताओं के बारे में कहा जाता था कि वह उस समय भारतीय राजनीति में अन्य नेताओं से कही ज्यादा आगे थे।

लाइफस्टाइल पर उठी उंगलियां

प्रमोद महाजन की लाइफस्टाइल पर भी कई बार उंगलियां उठाई गईं। उनके आलीशान रहन-सहन के ऊपर लोगों ने कमेंट किए। लेकिन वह बिना किसी फिक्र से आगे बढ़ते रहे। विवादों में भी उनका नाम कई बार उछला, लेकिन उन्होंने कभी भी उन विवादों को दबाने या छिपाने का प्रयास नहीं किया।

निधन

आपको बता दें बहुगुणी प्रतिभा के धनी प्रमोद महाजन की हत्या उनके ही छोटे भाई ने मुंबई में कर दी। वह अपने भाई के लिए सब कुछ हुआ करते थे। लेकिन 22 अप्रैल, 2006 को प्रमोद महाजन के आवास पर उनके भाई ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। प्रमोद महाजन के सीने में 3 गोलियां लगीं। इस दौरान उनकी पत्नी अंदर थीं। जिसके बाद वह 13 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। वहीं 3 मई 2006 को प्रमोद महाजन ने सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

पुस्तक विमोचन

कश्मीर का सही इतिहास बताती डॉ. आरएल भट्ट की किताब 'कश्मीर ऑफ्टर कल्हण' का विमोचन

जम्मू स्थित के एल सहगल हॉल में राइटर्स क्लब द्वारा आयोजित एक समारोह में डॉ. आरएल भट्ट की कश्मीर के इतिहास पर आधारित पुस्तक 'कश्मीर आफ्टर कल्हण' किया गया। प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकार, पद्मश्री डॉ. केएन पंडिता ने इस समारोह की अध्यक्षता की, जबकि एक अन्य विद्वान, डॉ. आरएल शांत मुख्य अतिथि थे। स्वागत भाषण संप्रति के अध्यक्ष आरएल जवाहर ने किया। उन्होंने डॉ. आरएल भट्ट को एक निडर लेखक बताया जिनके नाम विभिन्न विषयों पर एक दर्जन से अधिक पुस्तकें हैं।

मंच का संचालन शिक्षाविद प्रदीप कौल खुदबली ने किया। पुस्तक पर परिचयात्मक भाषण सह पेपर महान भाषाविद् प्रोफेसर पीएन ट्रिसल द्वारा पढ़ा गया। उन्होंने डॉ. भट्ट की उनके साहित्यिक कार्यों के लिए बहुत सराहना की और कहा कि लेखक एक प्रसिद्ध लेखक हैं और उन्हें संस्कृत के साथ-साथ फारसी पर भी महारत हासिल है।

उन्होंने कहा कि लेखक ने किताब लिखने से पहले कश्मीर के इतिहास का गहन अध्ययन किया है। यह कहते हुए कि कश्मीरी इतिहास में विकृतियाँ की गई हैं, उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्य और पृष्ठभूमि के साथ इसे उजागर करने के लिए भट्ट को श्रेय दिया। डॉ. आरएल भट ने अपने भाषण में कहा कि केएन पंडिता द्वारा किया गया बरिस्तान शाही का अनुवाद उनके लिए कश्मीर के इतिहास के गहन अध्ययन का आधार था और उन्होंने विभिन्न इतिहास की पुस्तकों का संदर्भ दिया, जिनका अध्ययन उन्होंने तथ्यों का पता लगाने और उन इतिहासकारों का मुकाबला करने के लिए किया था। कश्मीर के मूल इतिहास को विकृत करने का प्रयास किया।

उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को कश्मीर के इतिह-ास का अध्ययन करने और तथ्यों को जानने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम इतिह-ासकारों ने भी कश्मीर के हिंदू काल के बारे में तथ्यों को स्पष्ट रूप से रखा है, लेकिन कुछ ने बाद में उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश किया और लोगों में भ्रम पैदा किया।

उन्होंने कहा कि जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि हिंदू शासकों के काल में कश्मीर में कोई काला युग नहीं था, लेकिन वे इतने मजबूत और बहादुर थे कि एक अफगान योद्धा मोहम्मद गजनी भी कश्मीर में प्रवेश करने और उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सका।

डॉ. आरएल शांत ने लेखक के काम की सराहना करते हुए कहा कि यह पहली बार है कि संस्कृत और फारसी इतिहास एक साथ जुड़े हुए हैं और इसका श्रेय डॉ. भट्ट को जाता है।

त्यौहार

17 से 20 नवंबर तक मनाया जाएगा उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक आस्था का छठ महापर्व

देशभर में मनाएं जाने वाले दीपोत्सव पर्व के समापन के बाद अब अब लोगों को उत्तर भारत के तीन राज्यों में मनाए जाने वाले छठ का पर्व का बेसब्री से इंतजार है। छठ का पर्व मुख्य रुप में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। दिल्ली में रहने वाले प्रवासी भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। इस पर्व को झलक देश में अलग-अलग हिस्सों में भी दिखाई देती है।

छठ के इस व्रत को महिलाएं और माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए रखती हैं।

36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग चौबीस घंटो से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। ये व्रत कठिन व्रतों में से एक है। जानते हैं किस दिन कौन सी पूजा कब होगी।

कब है छठ पूजा

इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरूआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 09 बजकर 18 मिनट से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 07 बजकर 23 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को है।

17 नवंबर को है नहाय-खाय

लोक आस्था का यह महापर्व चार दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय-खाय होता है। इस साल नहाय-खाय 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 06 बजकर 45 मिनट पर होगा। वहीं सूर्यास्त शाम 05 बजकर 27 मिनट पर होगा।

18 को होगा खरना

खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 06 बजकर 46 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 05 बजकर 26 मिनट पर होगा।

19 को होगा डूबते सूर्य अर्घ्य

छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 05 बजकर 26 मिनट पर होगा।

20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य

चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का पारण का होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 06 बजकर 47 मिनट पर होगा।

मनोरंजक खबर- बॉलीवुड- टेलीविजन

एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं बॉलीवुड के ये भाई-बहन

रजनी वर्मा

फिल्म इंडस्ट्री में कई सेलेब्रिटी भाई-बहन ऐसे हैं, जो अक्सर अपनी बॉन्डिंग को लेकर लाइमलाइट बटोरते हैं। ये इंडस्ट्री के ऐसे सिब्लिंग्स हैं, जो एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस लिस्ट में अर्जुन-अंशुला, श्वेता नंदा-अभिषेक बच्चन, सलमान खान-अर्पिता खान शर्मा जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। चलिए भाई दूज के मौके पर बालीवुड के कुछ सेलेब्रिटी सिब्लिंग्स की बॉन्डिंग पर नजर डालते हैं।

श्वेता नंदा-अभिषेक बच्चन

श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन की एक-दूसरे संग काफी अच्छी बॉन्डिंग है। आए दिन दोनों एक दूसरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। अभिषेक-श्वेता अक्सर अपने लुक से स्टाइल गोल देते हैं। दोनों की तस्वीरों पर लोग अपना बेशुमार प्यार बरसाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्वेता अपने पिता अमिताभ बच्चन के ज्यादा करीब हैं और अभिषेक अपनी मां जया बच्चन के।

रिद्धिमा कपूर-रणबीर कपूर

रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर की जोड़ी भी बॉलीवुड की हिट और पॉपुलर भाई-बहन की जोड़ियों में से एक है। तस्वीरों से साफ नजर आता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। बता दें, अक्सर दोनों क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। एक्ट्रेस न होते हुए भी रिद्धिमा अक्सर बॉलीवुड पार्टीज में अपने परिवार के साथ नजर आती हैं। रिद्धिमा जितना क्लोज अपने भाई रणबीर के हैं, उतना ही वे अपनी भाभी आलिया के भी करीब हैं।

सुहाना-आर्यन-अबराम खान

शाह रुख खान और गौरी खान के बच्चे सुहाना खान, आर्यन खान और अबराम खान आए दिन चर्चा में रहते हैं। तीनों की बॉन्डिंग अक्सर फोटोज में देखने को मिलती है। आए दिन आर्यन और सुहाना बॉलीवुड इवेंट्स में साथ नजर आते हैं। इन दिनों सुहाना खान अपने डेब्यू को लेकर खबरों में बनी हुई हैं।

सलमान खान-अर्पिता खान शर्मा

भाई-बहन के रिश्ते की बात हो और सलमान खान-अर्पिता खान शर्मा का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सलमान अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। गणेश पूजा हो या फिर किसी की बर्थडे पार्टी सलमान, अर्पिता के साथ नजर आते हैं।

सारा और इब्राहिम अली खान

सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान अपने स्ट्रांग रिले-

शनशिप के कारण खूब लाइमलाइट में रहते हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत रिश्ता साझा करते हैं। आए दिन दोनों वेकेशन पर चिल करते नजर आते हैं। सारा अपने भाई इब्राहिम के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर पिक्चर्स और वीडियो शेयर करती रहती हैं।

अर्जुन कपूर-अंशुला कपूर

जैसा की आप सभी जानते हैं बोनी कपूर की दो शादियां हुई थीं और अर्जुन कपूर-अंशुला कपूर उनकी पहली पत्नी के बच्चे हैं। दोनों भाई-बहन की बॉन्डिंग हर किसी को बेहद लुभाती है। अर्जुन अपनी बहन अंशुला के काफी क्लोज हैं। भाई बहन की यह जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियो के कारण चर्चा में आ जाती है। दोनों की स्ट्रांग बॉन्डिंग के कारण लोग अर्जुन को अपनी बहन अंशुला की बैकबोन भी कहते हैं।

सैफ अली खान- सोहा अली खान

सैफ अली खान अपनी बहन सोहा अली खान के काफी करीब हैं। दिवाली हो, होली हो, राखी हो या फिर भाई दूज हर त्यौहार पर ये दोनों अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ नजर आते हैं। सोहा अपने इंस्टाग्राम पर भाई सैफ के संग खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

दीपावली पर टाइगर-3 की रिकार्ड तोड़ ब्लॉक बस्टर कमाई

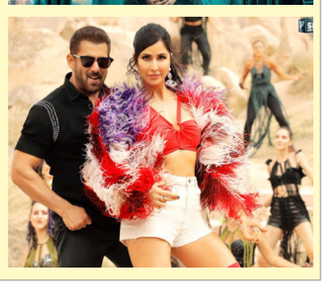

सलमान खान अभिनीत फिल्म टाइगर 3 ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 44.50 करोड़ रुपये की कमाई की। फिल्म निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) ने सोमवार को यह जानकारी दी। मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म रविवार को दीपावली के मौके पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई। खान के अलावा फिल्म में इमरान हाशमी और कैटरीना कैफ भी हैं।

फिल्म निमार्ताओं ने एक प्रेस नोट में कहा, टाइगर 3 ने हिंदी में 43 करोड़ रुपये और डब संस्करणों में डेढ़ करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे कमाई का कुल आंकड़ा 44.50 करोड़ रुपये हो गया। वाईआरएफ ने दावा किया कि फिल्म ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में दीपावली के दिन सबसे ज्यादा कमाई की। 'टाइगर 3' 2017 की फिल्म टाइगर जिंदा है की अगली कड़ी है। फिल्म के टिकटों की अग्रिम बुकिंग पांच नवंबर को शुरू हुई थी। फिल्म निर्माण कंपनी ने यह भी कहा कि टाइगर 3 को सलमान की फिल्म के साथ-साथ टाइगर फ्रेंचाइजी की किसी भी फिल्म के लिए 'सबसे बड़ा ओपनिंग डे' मिला।

उड़िया अभिनेत्री मौसमी नायक ब्लैकमेल करने के आरोप में हुई गिरफ्तार

उड़िया फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मौसमी नायक को एक युवा महिला लेखिका को ब्लैकमेल करने और उसकी सार्वजनिक छवि को बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं उन पर बनस्मिता के पति के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप है। भुवनेश्वर के डीसीपी कार्यालय ने कहा कि भुवनेश्वर में इन्फोसिटी पुलिस ने लेखक की शिकायत के आधार पर 39 वर्षीय अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लिया है। मौसमी नायक ने पहले इन्फोसिटी पुलिस में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि लेखिका उसके 5.08 लाख रुपये चुकाने में विफल रही है। इसके बाद, अभिनेत्री ने दोनों पक्षों के आश्वासन के साथ एक समझौता याचिका पर हस्ताक्षर करने के बाद अपनी शिकायत वापस ले ली थी। पुलिस ने कहा कि लेखिका ने अभिनेत्री को पैसे भी लौटा दिए थे और मौसमी ने विश्वास दिलाया था कि वह लेखिका की छवि खराब करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगी। हालांकि, अपने पैसे वापस मिलने के बाद भी, अभिनेत्री ने मीडिया के सामने लेखिका और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बयान दिए और बनास्मिता पति के खिलाफ चंदका पुलिस स्टेशन में झूठा मामला भी दर्ज कराया।

सार समाचार

जामिया मिलिया इस्लामिया कुलपति नजमा अख्तर हुई सेवानिवृत्त, इकबाल बने कार्यवाहक

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। देश के प्रतिष्ठिक शैक्षणिक संस्थान जामिया मिलिया के उप कुलपति इकबाल हुसैन ने नजमा अख्तर के सेवानिवृत्त होने के बाद सोमवार को विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति का पदभार संभाल लिया। अख्तर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति थीं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नए कुलपति की नियुक्ति होने तक हुसैन कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कामकाज संभालेंगे।

अख्तर को अप्रैल 2019 में पांच साल या 70 वर्ष की आयु तक के लिए कुलपति नियुक्त किया गया था। बयान में कहा गया है कि 12 नवंबर 2023 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति के तौर पर प्रोफेसर नजमा अख्तर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इकबाल हुसैन नयी नियुक्ति तक कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कार्यभार संभालेंगे।

नहीं रहे बीकानेरवाला के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। मिठाई और स्नैक्स ब्रांड कंपनी बीकानेरवाला के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। केदारनाथ अग्रवाल 86 वर्ष के थे। बीकानेरवाला की ओर से एक बयान जारी कर कहा गया कि काकाजी के नाम से जाने जाने वाले केदारनाथ अग्रवाल का निधन एक ऐसे युग के अंत का प्रतीक है। जिसने स्वाद को समृद्ध किया और अनगिनत जिंदगियों को प्रभावित किया।

जानकारी के लिए बता दें कि भारत में बीकानेरवाला की 60 से अधिक दुकानें हैं। इनके आउटलेट्स अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) जैसे देशों में भी मौजूद हैं। केदारनाथ अग्रवाल ने अपना व्यावसायिक सफर देश की राजधानी दिल्ली से शुरू किया था।

विश्व मधुमेह दिवस से दिल्ली एम्स में फ्री मिलेगी इंसुलिन

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने मधुमेह के शिकार गरीब मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। एम्स के किसी भी ओपीडी पर एंसुलिन की फ्री सुविधा मिलेगी। एंसुलिन का इंजेक्शन मधुमेह के शिकार मरीजों को दिया जाता है। एम्स में दो नए काउंटर खुलेंगे। जो न्यू राज कुमार अमृत कौर ओपीडी बिल्डिंग से सामने होंगे।

यह काउंटर हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा, इंसुलिन काउंटर पर इंसुलिन की शीशियों पर हिंदी और अंग्रेजी में लिखने की सलाह भी देगा। जो मरीज काफी दूर से आते हैं। ऐसे मरीजों को आईस पैक दिया जाएगा। ताकि वह आसानी से इंसुलिन को लेकर जा सकें।

जानकारी के लिए बता दें कि प्रिस्क्राइब करने वाला चिकित्सक इस बात की जानकारी देंगे कि उस मरीज को कोई शीशियां नहीं दी जाएंगी। केंद्र उन्हें उपलब्ध कराएगा। शुरूआत में इंसुलिन की शीशियां एक महीने की उपचार अवधि के लिए जारी की जाएंगी, जिसे भविष्य में 2-3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

दिल्ली में प्रदूषण पर प्रहार या जेब पर मार

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर एनडीएमसी ने वायु गुणवत्ता की मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और वायु गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए निजी वाहनों की पार्किंग फीस दोगुनी कर दी है। 31 जनवरी तक पार्किंग फीस दोगुनी ली जाएगी। इसके पीछे नई दिल्ली इलाके में निजी वाहनों का आवागमन कम करने की मंशा है।

एनडीएमसी ने अपनी पार्किंग में निजी वाहन खड़े की फीस दोगुनी करने का आदेश सोमवार को जारी किया। एनडीएमसी ने तर्क दिया है कि आयोग ने 21 अक्तूबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संशोधित कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इसके तहत निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का प्रावधान किया गया था। आयोग की उप समिति ने चार नवंबर को दिल्ली का औसत एक्यूआई 415, पांच नवंबर को औसत एक्यूआई 454 मिला। इतना ही नहीं, अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण एक्यूआई के बढ़ने और गंभीर श्रेणी में बने रहने की उम्मीद जताई गई।

एनडीएमसी की ओर से एक घंटे की कार की पार्किंग फीस 20 रुपये और दुपहिया की पार्किंग फीस 10 रुपये ली जाती है। इसके बाद प्रति घंटे कार की पार्किंग फीस में 20 रुपये व दुपहिया की पार्किंग फीस में 10 रुपये बढ़ोतरी का प्रावधान है, मगर पांच घंटे के बाद पार्किंग फीस में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं है। लिहाजा अब पार्किंग में एक घंटे तक कार खड़ी करने पर 40 रुपये देने होंगे और दुपहिया खड़ा करने पर 20 रुपये फीस देनी पड़ेगी। चार से अधिक समय तक कार की फीस दो सौ रुपये और दोपहिया की सौ रुपये चुकानी पड़ेगी।

दीवाली के बाद अब छठ घाट सजाने की तैयारी

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। दीपावली खत्म होते ही छठ महापर्व को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोग इसके लिए तैयारियों की शुरूआत में लग गए हैं। यूपी-बिहार से सटे राज्यों में इस महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चूंकि, राजधानी दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचली रहते हैं, तो यहां भी छठ पर्व को बड़ी ही आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। समय के साथ-साथ यह और भी बड़े पैमाने पर आयोजित होने लगा है। पूर्वांचलियों के इस महापर्व में किसी प्रकार की असुविधा और कमी न रह जाए इसके लिए दिल्ली सरकार ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार लगभग एक हजार छठ घाटों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री आतिशी ने छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है जिसमें कई विधायकों और विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। आतिशी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी छठ पूजा आयोजन समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय करें और छठ घाटों तैयार किये जाने के कामों में तेजी लाकर अन्य व्यवस्थाओं को भी मुहैया करवाएं।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अंतिम समय मे किसी प्रकार की कमी न रह जाये या श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इसके लिए आयोजक समिति से सुझावों को लेकर उनके अनुरूप छठ घाटों को तैयार कराया जाए और घाटों पर साफ-सफाई की भी समुचित व्यवस्था की जाए। ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूरे श्रद्धा-भाव से इस महापर्व को मना सकें। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में एक हजार छठ घाटों को तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। वहीं कुछ ऐसे भी छठ घाट हैं जिन्हें स्थानीय लोग मिलकर बना रहे हैं। उनमें से एक है कुतुब विहार का छठ घाट जहां लोग आपसी सहयोग से छठ घाट के निर्माण कार्य मे जुटे हुए हैं। उन्हें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है।

दिल्ली में खूब छूटे पटाखे एनसीआर में फिर छाया दमघोंटू प्रदूषण

दीवाली की आतिशबाजी और पड़ोसी राज्यों के कारण सांसे हुई भारी, जारी रहेगा ग्रेप-4

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिवाली पर राजधानी में पटाखे चलाए जाने के चलते एकाएक प्रदूषण में हुए इजाफे के बाद सोमवार को दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों संग बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण का ठीकरा दीवाली पर हुई आतिशबाजी और पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर फोड़ा। मीडिया से बातचीत के दौरान पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ग्रिड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-4 (ग्रेप-4) के तहत प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर में आगे भी जारी रहेंगे।

राजधानी में एंटी डस्ट कैंपेन को अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों की छुट्टियां आगे बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। गोपाल राय ने कहा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अगले आदेश तक दिल्ली में ग्रेप 4 नियमों के तहत प्रदूषण-विरोधी उपाय लागू रहेंगे। इसके तहत बीएस-3 पेट्रोल वाहनों और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सामान ले जाने वाले और आवश्यक सेवाओं से जुड़े ट्रकों को छोड़कर अन्य सभी ट्रक दिल्ली में प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार?

दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर पर्यावरण मंत्री ने कहा, 'दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध है। पटाखे यूपी और हरियाणा से दिल्ली लाए गए थे। दिल्ली, हरियाणा और यूपी की पुलिस बीजेपी के नियंत्रण में और इन तीन पुलिस बलों की निगरानी के बीच कोई भी आम आदमी आसानी से पटाखों की आपूर्ति नहीं कर सकता है। कुछ विशिष्ट लोगों ने ऐसा किया है। अगर वह सक्रियता से काम करते तो रातों रात प्रदूषण में 100 अंकों की बढ़ोतरी से हम बच सकते थे।'

ऑड-ईवन कब होगा लागू?

रिव्यू मीटिंग के बाद एएनआई से बात करते हुए गोपाल राय ने कहा, 'बैठक में दिल्ली-एनसीआर में समग्र वायु गुणवत्ता स्थिति पर चर्चा शामिल होगी। हम प्रदूषण से निपटने के लिए लागू किए गए विभिन्न प्रवर्तन कार्यों की स्थिति पर चर्चा करेंगे।' दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि अगर हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' हो जाता है तो सरकार दिल्ली में परिवहन को नियंत्रित करने के लिए ऑड-ईवन नियम को लागू करने पर फिर से विचार कर सकते है।

प्रगति मैदान में सज गए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के मंडप, 27 नवंबर तक चलेगा

संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला मंगलवार से शुरू हो जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल व सोम प्रकाश इसका उद्घाटन करेंगे। शुरूआती पांच दिन 14-19 नवंबर को व्यावसायिक दिन होगा। इस दौरान यहां केवल बी-टू-बी गतिविधियां होंगी। 19-27 नवंबर को मेले में आम लोगों को एंट्री मिलेगी।

ट्रेड फेयर के लिए प्रगति मैदान के 1 से 14 नंबर हॉल सज गए हैं। भारत मंडपम के ऑडिटोरियम-2 में उद्घाटन समारोह होगा। इसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरौला की मौजूदगी में दोनों केंद्रीय मंत्री मेले का आगाज करेंगे। इस बार क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा ट्रेड फेयर आयोजित होने जा रहा है, जिसका आकार करीब 1.10 लाख वर्ग मीटर रहेगा। इसमें करीब 370 कंपनियां, 3500 वितरक, सभी प्रदेशों व केंद्र शासित राज्यों और 13 विदेशी पवेलियन शामिल हैं।

खादी का पवेलियन सबसे बड़ा

हॉल नंबर तीन पूरा खादी पवेलियन है। ये सबसे बड़ा पवेलियन है, जिसका आकार पिछली बार से करीब चार गुना बड़ा है। इस अकेले पवेलियन में देश के हर जिले का उत्पाद मिल जाएगा। हस्तशिल्प, हथकरघा से निर्मित वस्त्र, साबुन, अगबत्ती, शहद, खाने-पीने के सामान इसके अंदर मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश का पवेलियन भी भव्य

उत्तर प्रदेश पवेलियन क्षेत्रफल के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। इसमें 16 फुट ऊंची राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई है। हॉल नंबर दो के दो तिहाई हिस्से में ये पवेलियन है। एक जिला एक उत्पाद की नीति के लिहाज से हर जिले के स्टाल इसमें होंगे। जिले के मशहूर सामान इसमें मिलेंगे।

मेले में सुनने को मिलेगी मन की बात

पीएम मोदी के मन की बात भी मेले में सुनने को मिलेगी। हॉल पांच में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पवेलियन में इसके लिए अलग कॉर्नर स्थापित किया गया है। यहां मन की बात का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मंत्रालय का पवेलियन भव्य बनाया है। कोयला मंत्रालय सहित बाकी मंत्रालयों के पवेलियन भी खास हैं।

पहले तल पर सभी राज्यों के पवेलियन

हॉल दो से पांच के पहले तल पर सभी राज्यों के पवेलियन हैं। यहां हरियाणा पवेलियन खासा आकर्षक है। इस चारों ओर से लालटेन से सजाया है। ताऊ की बैठक, हुक्के का इंतजाम है। खाट है, भैंस भी है। एथलीट भी हैं। राज्य की प्रगति की रिपोर्ट भी दिखेगी।

बच्चों के लिए खेलने की अलग जगह

पहली बार ट्रेड फेयर में बच्चों के लिए खेलने की अलग जगह भी बनाई गई है। हॉल पांच के पहले तल पर द टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किड्स जोन तैयार किया है। 10 साल तक के बच्चे यहां फ्री राइडिंग कर सकते हैं। आईटीपीओ ने इसके लिए फ्री स्पेस उपलब्ध कराया है।

साथ में जमेगा सरस मेले का रंग

हॉल सात ए बी सी में ट्रेड फेयर के साथ सरस मेले का रंग भी जमेगा। इसमें लघु एवं मध्यम उद्योगों के तहत देश के हर जिले में निर्मित सामान मिलेंगे। खासकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बनाए गए सामान इस मेले में खरीदे जा सकते हैं।

भाई दूज व छठ पर्व
की हार्दिक शुभकामनाएं

जोगेन्द्र सोलंकी

रोविंग एडिटर, दैनिक देशबन्धु
निदेशक, जेनेसिस मीडिया प्रा. लि.
निदेशक, क्रास रोड्स कम्यूनिकेशंस

अध्यक्ष
दिल्ली क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन

@to_jogi @jogisolanki jogindersolanki@gmail.com 9810167025

भाई बहन के अटूट प्रेम और सर्मपण के प्रतीक
भाई दूज
चार दिवसीय लोक आस्था के महापर्व
छठ पूजा
की हार्दिक शुभकामनाएं

सुनील कुमार शर्मा
विधायक साहिबाबाद

सभी नगरवासियों को
भाई दूज व छठ पर्व की
हार्दिक शुभकामनाएं

आइए
अपने शहर को स्वच्छ व
सुंदर बनाने का
संकल्प लें

अजीत निगम (पार्षद)
नगर निगम गाजियाबाद
वार्ड -96

जंगल में चरने वाली गीर गाय का शुद्ध बिलोना घी

Jungle Grazing
NATURE'S TREASURE
A-2 Gir Cow
Vedic Bilona GHEE

Ayurvedic
Immunity
Booster

मस्तिष्क संबंधी, त्वचा व केश संबंधी, पेट संबंधी व जोड़ संबंधी इत्यादि समस्याओं के निदान में सहायक हमारे जंगल में विचरण करती गौ माता के दूध से बना घी अमृत समान होता है, गौ माता के साथ किसी प्रकार की क्रूरता नहीं होती बल्कि वह अपने झुंड के साथ प्राकृतिक परिवेश में बिना बंधन प्रसन्न चित्त रहती हैं।

on Special Discount Today

For Export Order & Distributorship +91 9910850446

www.naturestreasure.in

सार समाचार

मास्टर प्लान को नियोजन विभाग का जल्द ही मिलेगा ग्रीन सिग्नल

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। जल्दी ही जीडीए का मास्टर प्लान फाइनल होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इस मास्टर प्लान को जीडीए फाइनल कर देगा। इससे पहले ही मास्टर प्लान गाजियाबाद को लेकर आपत्तियां मांगी गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी। इससे पहले लोनी और मोदीनगर प्लान पूरी तरह से फाइनल हो गया था। हालांकि अभी विधिवत तौर पर प्लान फाइनल नहीं माना जाएगा। गाजियाबाद के साथ ही लोनी और मोदीनगर का प्लान फाइनल माना जाएगा। ऐसे में अब गाजियाबाद मास्टर प्लान के लिए मांगी गई आपत्तियों की सुनवाई के बाद अब मास्टर प्लान को फाइनल करने की कोशिश में जीडीए लगा हुआ है। जीडीए की कोशिश है कि गाजियाबाद मास्टर प्लान फाइनल होने के साथ ही कार्रवाई आगे की जाएगी। वहीं सूत्रों का कहना है कि आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद जो भी ड्राफ्ट फाइनल होगा उसकी जांच कराई जाएगी। अगर नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय कमेटी फाइनल कर देगी तो इसके बाद डीएम इसके फाइनल करेंगे। इसके बाद इस प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में पेश किया जाएगा। बोर्ड की बैठक में नियोजन के मास्टर प्लान के फाइनल होने के बाद ही शासन स्तर से इसको ओके किया जाएगा।

नीदरलैंड की कंपनी को अभी नहीं मिलेगा गालंद में कब्जा

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। गालंद एरिया में कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने का प्लान फंस गया है। कई कोशिश के बाद भी नगर निगम को इस प्लांट को लगाने के लिए जमीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। पिछले कई वर्ष से नगर निगम इस कोशिश में लगा है इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। गालंद में नगर निगम प्रशासन ने करीब 35 एकड़ जमीन खरीदी है। इस जमीन पर ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने का कार्य किया जाना था। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने के लिए नीदरलैंड की एक कंपनी को ठेका दिया गया था। कंपनी ने यूपी सरकार के साथ इसके लिए एमओयू साइन किया था। एमओयू साइन हुए भी अब पांच वर्ष पूरे हो चुके है। कंपनी अब गालंद में प्लांट लगाने के लिए जमीन पर कब्जा मांग रही है। कंपनी के कब्जा मांगने के बाद भी कई बार नगर निगम प्रशासन की कोशिश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि इसके लिए कई बार शासन की ओर से भी प्लांट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की कोशिश की है। कई बार शासन से भी जमीन पर कब्जा दिलवाने के लिए निवेदन निगम प्रशासन की ओर से दिया गया है। मगर इसके बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ पाया है। अब माना जा रहा है कि फिर से हो सकता है कि शासन अपने स्तर से इस जमीन पर कब्जा दिलवाने की कोशिश करे। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद ही शासन इस मामले में कदम उठाने जा रहा है।

जीडीए नीलामी में 13.65 करोड़ में बिके मधुबन बापूधाम योजना के 8 भूखंड

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। जीडीए के विभिन्न योजनाओं में रिक्त व्यवसायिक भूखंड, कन्वीनियेंट शॉपिंग भूखंड,दुकान,आवासीय भूखंड, पेट्रोल पंप आदि संपत्तियों को बेचने के लिए आयोजित की जा रही नीलामी में मधुबन-बापूधाम योजना के सर्वाधिक भूखंड लोग खरीद रहे है। शुक्रवार को लोहियानगर स्थित हिंदी भवन में आयोजित खुली बोली के तहत नीलामी में मधुबन-बापूधाम योजना के 6 व्यवसायिक व 2 आवासीय भूखंड समेत 8 भूखड़ों को बोलीदारों ने सर्वाधिक बोली लगाकर खरीदा।नीलामी में बिक्री किए गए इन 8 भूखंडों से जीडीए को 13.65 करोड़ रुपए की आय हुई।

जीडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी की अध्यक्षता में ओएसडी सुशील कुमार चौबे, प्रभारी चीफ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह,टाउन प्लानर राजीव रतन शाह,सहायक अभियंता विनय वर्मा,लेखाकार योगेंद्र कुमार,वरिष्ठ सहायक प्रभात चौधरी,रामबीर आदि की मौजूदगी में नीलामी की गई। नीलामी में करीब 30 आवेदकों ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक टोकन लिए। इसके बाद सीलबंद निविदाएं प्राप्त की गईं। नीलामी करीब 12.30 बजे शुरू की गई।

जीडीए अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि नीलामी में बोलीदाता का मधुबन-बापूधाम योजना के व्यावसायिकऔर आवासीय भूखंड को खरीदने में सबसे अधिक उत्साह दिखा। इस दौरान योजना में 6 व्यवसायिक और दो आवासीय भूखंड को बोली लगाकर बोलीदारों ने खरीद लिया।इन भूखंडों की बिक्री होने के बाद 13.65 करोड़ रुपए की आय हुई। जीडीए अपर सचिव ने बताया कि जीडीए की संपत्ति खरीदारों को पसंद आ रही है। रिक्त पड़े भूखंड इच्छुक खरीदार खरीद रहे हैं। त्योहारी सीजन में अब प्रत्येक शुक्रवार को नीलामी में संपत्ति बिक रही हैं।

एनएचएआई के टोल बूथों पर मनमानी

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सड़कें बनने के बाद आम लोगों का सफर जहां आसान हो गया है, वहीं दूसरी तरफ टोल कंपनियों की मनमानी के चलते जनता त्रस्त है और टोल रोड से चलना उसकी जेब पर भारी पड़ने लगा है। अधिकारी यह कह कर बच जाते हैं कि वे जांच करेंगे कि गड़बड़ कहां हुई है।

बात दीपावली के दिन रविवार की है। गाड़ी यूपी 14 ईएस- 7650 भोजपुर से दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ी और गाजियाबाद में लैंड क्राफ्ट के पास उतरकर गाजियाबाद आ गई। लेकिन रात में जब टोल कटने का मैसेज आया तो गाड़ी मालिक चकरा गया। जो टोल काटा गया वह मेरठ से दिल्ली तक 135 रुपये का काटा गया। गाड़ी को शाम 14.26 बजे सराय कालेखां पर बताया गया, जबकि उस समय यह गाड़ी गाजियाबाद के राजनगर और लोहियानगर में थी। इसी प्रकार गाजियाबाद के रहने वाले उमेश कुमार की गाड़ी यूपी 14बीएस 1027 घर की पार्किंग में गाजियाबाद खड़ी थी। उसी दिन दस नवंबर को उनके मोबाइन पर मैसेज आता है कि रोनाही टोल पर 115 रुपये का उनका टोल कट गया। इसकी शिकायत उमेश कुमार एनएचएआई को कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई परिणाम नहीं निकला।

बात यहीं तक नहीं रूकती। आर भारत के पत्रकार अर्जुन चौधरी की गाड़ी डासना में थी और उनका 170 रुपये का टोल कट गया। ये घटनाएं तो बानगी मात्र है। बता दें कि ये तीनों घटनाएं पत्रकारों के साथ ही घटित हुई जिनका पता चल गया। आम जनता के साथ तो प्रति दिन लगता है कि टोल कंपनियां लूट करती है, लेकिन किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं हो रही।

इसके साथ ही वेस्टर्न टोल प्लाजा और सांपला टोल प्लाजा पर भी स्थिति ठीक नहीं है। वहां से भी एनएचएआई के पास शिकायतें की गई, लेकिन समाधान किसी की भी नहीं हुआ। इस स्थिति में लोग सोचते हैं कि टोल रोड पर जाकर क्यों अपनी जेब कटवाई जाये। रोहित सिंह कहते हैं कि टोल कंपनियां मनमानी करती है और अधिक टोल काटती है, लेकिन उनके खिलाफ न तो सरकार कार्रवाई करती है और न ही एनएचएआई के उच्चाधिकारी।

सूत्रों के अनुसार रविवार को दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वे पर मनमाना टोल काटने को लेकर एनएचएआई के उच्चाधिकारियों के पास शिकायत पहुंचने के बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। लेकिन देखना यह होगा कि कार्रवाई क्या होती है।

दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वे, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार से इस संबण में बात की गई तो उन्होंने कहा दिल्ली- मेरठ एक्सप्रेस वे पर गलत टोल कैसे काटा गया यह जांच का विषय है। इस प्रकरण की जांच करवाई जायेगी। इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा। पूर्व में ऐसी कोई घटना हुई है तो इसकी जानकारी नहीं है।

14 नवंबर को गाजियाबाद जनपद की वर्षगांठ पर विशेष

47 साल की विकास यात्रा में ऐसे बदल गई गाजियाबाद की सूरत

सुशील कुमार शर्मा (स्वतन्त्र पत्रकार)

गाजियाबाद। 14 नवम्बर 1976 को गाजियाबाद जिला बना। इस वर्ष 47 वीं वर्षगांठ है। जिला बनने से पहले यह मेरठ जिले की तहसील था। 1975 में आपातकाल से पूर्व इसे सब-जिला बनाकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के जन्मदिन पर 14 नवम्बर (बाल दिवस) पर विधिवत जिला घोषित किया गया। उस समय गाजियाबाद में शामिल हापुड़ जिला, गाजियाबाद की तहसील था। बाद में गठित जिला गौतम बुद्धनगर भी गाजियाबाद जनपद का हिस्सा रहा।

गाजियाबाद जनपद प्रारम्भ से उद्योग नगर था। 1970 के दशक में जब पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन चरम सीमा पर था कलकत्ता के बहुत से उद्योग गाजियाबाद आ गये थे। कानपुर तब अविभाजित उ.प्र. की प्रथम उद्योग नगरी थी। जहां से प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था। यह वह समय था जब कानपुर का स्थान गाजियाबाद ने ले लिया था।

उस समय गाजियाबाद के सांसद बी. पी. मौर्य थे तथा विधायक प्यारे लाल शर्मा थे। देश की राजधानी समीप होने के कारण गाजियाबाद की खबरें राजधानी के अखबारों में प्रमुखता से छपती थी। बड़े उद्योगों के आने के बाद यहां के सफेदपोश अपराधी फिरौती और अपहरण में सक्रिय हो गये, जिसका नतीजा गाजियाबाद अपराध नगरी के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गया। उद्योग पलायन करने लगे। श्रमिक यूनियनें भी इन्हीं सफेदपोश अपराधियों के संरक्षण में थी। जिससे धड़ाधड़ उद्योग बंद होते चले गये।

गाजियाबाद के चेयरमैन और बाद में महानगर बनने पर मेयर , विधायक और सांसद रहे अधिकांश जनप्रतिनिधियों ने नगर और जनपद के विकास के स्थान पर अपना और अपने परिवार की सम्पत्ति का बेहिसाब विस्तार किया। आज सभी

धनकुबेर हैं। वर्तमान विधायक भी प्रदेश में मंत्री रहे हैं, सांसद केन्द्र में मंत्री हैं। दोनों चाटूकारों के शिकंजे में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें सब हरा-हरा दिखाई देता है।

गाजियाबाद के लोगों को जीडीए के उपाध्यक्ष रहे धर्मेंद्र देव को नहीं भूलना चाहिए जिनके कार्यकाल में यह नगर , महानगर बना। जीडीए के साथ-साथ तब वह नगर निगम के भी प्रशासक थे। तभी उन्होंने महानगर की योजना बनाई थी। गाजियाबाद की तमाम नई-नई कालौनियां भी धर्मेंद्र देव के काल में ही घोषित की गयी थी। गाजियाबाद में एक समय ऐसा रहा जब शहर में बड़े-बडे उद्यमियों की मौजूदगी के बावजूद शहर रहीस बी.बी. बिन्दल (माडर्न इंडस्ट्रीज), हरियन्त चौधरी (चौधरी सिनेमा व चौधरी भवन के मालिक) व राजेन्द्र मंगल (फिल्म फाइनेंसर) ही जाने जाते थे। राजेन्द्र मंगल की चौधरी मोड़ स्थित कोठी पर जिले के आला पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की दावतों का आयोजन होता था।

समय के साथ गाजियाबाद का स्वरुप तेजी से बदला है। माल, मल्टीफ्लेक्स, फ्लाई ओवरों, मैट्रो, रेपिड रेल, एलिवेटिड रोड, बाई पास, आकाश छूती 26 मंजिली इमारतें तथा इससे भी ऊंची बनती इमारतों में गाजियाबाद से ज्यादा दिल्ली में नौकरी और अपना रोजगार कर रहे लोगों का बसेरा है। दिल्ली से सटी कालोनियों में रहने वालों का गाजियाबाद शहर से कम दिल्ली आवागमन ज्यादा रहता है। गाजियाबाद निवासी देश के ख्यातिप्राप्त कथाकार से रा यात्री, देश के ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तलवार, दिवंगत ओज के राष्ट्रीय कवि कृष्ण मित्र, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त गजलकार दिवंगत डॉ कुंअर बेचैन ऐसी शख्सियत हैं। जिन्होंने गाजियाबाद का नाम रोशन किया है।

गाजियाबाद बनने से पहले भी और अब भी पत्रकार व हिन्दी सेवी गोपाल कृष्ण कौल, गुरशरण लाल अदीब, मेंहदी नज्मी, शम्स गाजियाबादी, इशरत किरतपुरी, रामेश्वर उपाध्याय, चन्द्र दत्त इन्दु, हर प्रसाद शास्त्री, चन्द्र भान गर्ग, श्याम सुन्दर वैद्य (मेरे पिता जो तडक वैद्य के नाम से मशहूर थे), चिरंजी लाल पाराशर, योगेन्द्र पाल बागी, कैलाश आजाद, मधू सुदन दयाल सम्पादक, ब्रह्मा नंद पंत, शिव कुमार गोयल, तेलूराम काम्बोज, डॉ श्याम निर्मम, प्रेम किशोर पटाखा, विनय संकोची, मासूम गाजियाबादी, जमील हापुडी, धनंजय सिंह, गोविंद गुलशन, रमा सिंह, जकी तारीक व सुभाष चन्दर के कारण प्रसिद्ध है।

वर्तमान में प्रमोद शर्मा, विद्या शंकर तिवारी, अशोक निर्वाण , गगन सेठी राष्ट्रीय चैनल और राष्ट्रीय अखबारों में गाजियाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। गाजियाबाद के महाविद्यालयों के प्राचार्य रहे दिवंगत गुरूदेव बी. एस. माथुर, आर. बी. एल. गोस्वामी व बी. एस. गोयल, चौधरी चरणसिंह विश्व विद्यालय के उपकुलपति रहे हैं। वर्तमान में अनेक साहित्यिक संस्थायें महानगर, हिन्डनपार व लाइनपार में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार एवं फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त संगीतज्ञ पंडित हरिदत्त शर्मा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निर्देशक रहे दिनेश खन्ना, प्रख्यात रंगकर्मी व अभिनेता आभूषण, सुरेन्द्र पाल सिंह, निशी कान्त दीक्षित, प्रेम प्रकाश कुमार के कारण भी गाजियाबाद का नाम रोशन है।

राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने गिनाई अपने विभाग की उपलब्धियां

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के पिछडा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार ने एक प्रेसवार्ता के दौरान अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई हैं। राज्यमंत्री ने कहा कि पहले उनसे सीएम योगी ने सौ दिन से लेकर पांच साल तक का विभाग के कार्यो का रोडमैप मांगा था।

जब हमने सौ दिन का कार्य करके दिखाया जो फिर पांच साल तक के कार्यो पर सीएम ने हरी झंडी दी। इसी कडी में जगतगुरु रामभ्रदाचार्य द्वारा स्थापित चित्रकूट में स्थापित दिव्यांग विवि को यूपी सरकार ने राज्य विवि के रूप में मान्यता प्रदान की है कि अब प्रदेश में दिव्यांगों की उच्च शिक्षा के लिए दो दिव्यांग पुनर्वास विवि हैं। इसके अलावा दिव्यांग दम्पत्तियों की शादी प्रोत्साहन योजना के लिए पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य था, जिससे दिव्यांगों को कठिनाईयों का सामना करना पडता था लेकिन अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है और डेढ सौ करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है जिससे इस बार ७५ हजार दिव्यांगों की शादी हो सकेगी।

इसके अलावा दिव्यांगों की समस्या निस्तारण के लिए मोबाइल कोर्ट गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी आदि जनपदों में संचालित की जा रही है। इसके अलावा डॉ.शकुंतला विवि में छात्रों की बढती संख्या को देखते हुए 48 करोड रुपए की लागत से नया महिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं विश्व विद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 112 छात्रों को प्लेसमेंट के माध्यम से कॉरपोरेट कम्पनियों में जॉब दिलाई गई है। स्मार्ट क्लास के जरिए भी छात्रों को उन्नत शिक्षा दिलाई जा रही है। पिछडा वर्ग की स्कारलशिप के लिए इस बार 435 करोड अतिरिक्त बजट की व्यवस्था की गई है। व अन्य कार्यो के लिए 167 करोड बजट बढाया गया है। पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र व छात्राओं के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में ऐसे छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु विशेष प्रयास कर 1.25 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था पहली बार करायी गई है। प्रेसवार्ता में भाजपा महानगर कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता, मंत्री प्रतिनिधि सौरभ जायसवाल, समाजसेवी वीके अग्रवाल, प्रदेश मीडिया प्रभारी विशाल कश्यप आदि मौजूद रहे।

गीले व सूखे कूड़े का निस्तारण कर जीरो वेस्ट बनाएगा जीडीए

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। जीडीए दफ्तर एवं ऑफिसर्स कॉलोनी को जीरो वेस्ट बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कम्पोस्टर के जरिए गीला व सूखे कूड़े का निस्तारण कर जीरो वेस्ट बनाया जा सकेगा। जीडीए प्रांगण में तैयार किए गए चार कम्पोस्टर का सचिव राजेश कुमार सिंह ने अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, ओएसडी गुंजा सिंह, उद्यान प्रभारी एसके भारती, अधिशासी अभियंता प्रशांत गौतम,अधिशासी अभियंता आरके सिंह, अधिशासी अभियंता राजकुमार वर्मा आदि की मौजूदगी में फीता काटकर उद्घाटन किया गया। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जीडीए द्वारा अभियंता दिवस पर शपथ ली गई कि जीडीए ऑफिस और ऑफिसर्स कॉलोनी को जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य दीपावली से पहले शुरू कर दिया जाएगा। इसी क्रम में उद्यान अनुभाग द्वारा चार कम्पोस्टर को तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि इन कम्पोस्टर में गीला व सूखे कूड़े का निस्तारण किया जा सकेगा। इससे खाद बनाई जाएगी। यह खाद ग्रीन बैल्ट,पार्कों से लेकर सेंट्रल वर्ज में लगे पेड़-पौधों के इस्तेमाल में आएगी। जीडीए सचिव ने जीडीए के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग डस्टबिन में डालें ताकि जीडीए कार्यालय एवं ऑफिसर्स कॉलोनी को जीरो वेस्ट बनाया जा सकें।

सार समाचार

आईएएस अफसर ऋतु सुहास ने मॉडल बनकर सीता के रूप में किया कैटवॉक

संवाददाता @visheshkhabar.in

लखनऊ। रेशम निदेशालय एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित फैशन शो में आईएएस अधिकारी ऋतु सुहास ने सीता के रूप में कैट वॉक किया और दिग्गज मॉडल्य को फेल कर दिया।

बता दें कि आईएएस अधिकारी ऋतु सुहास हर दिन कुछ नया करने में विश्वास करती है। उनके पति वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुहास एल वाई बैडमिंटन में देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं।

मंगलवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान स्थित जूपिटर हॉल में रेशम निदेशालय एवं खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा भव्य फैशन शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर विकास निदेशालय में अपर निदेशक एवं आईएएस अधिकारी ऋतु सुहास ने खादी परिधानों के साथ रैंप पर उड़ान भरी। वे इससे पहले भी अनेक फैशन शो में हिस्सा ले चुकी है तथा उनकी हर तरफ सराहना ही हुई है। इसके साथ ही बता दें कि वे किसी भी विभाग अथवा पद पर हो कुछ न कुछ नया करने की सोचती है। फैशन शो में मशहूर फैशन डिजाइनर आस्मा हुसैन एवं अदिति जग्गी रस्तोगी द्वारा भी प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए रेशम एवं खादी परिधानों का मशहूर मॉडल द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

आमरण अनशन पर बैठे जनसंख्या अनुसंधान फाउंडेशन के अध्यक्ष ने की पीएम के सलाहकार से मुलाकात

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। लाजपत नगर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने प्रधानमंत्री के सलाहकार से मुलाकात की। वह सोमवार सुबह प्रशासनिक एंबुलेंस से दिल्ली के लिए रवाना हुए।

दिवाली के दिन भी वह अनशन पर बैठे रहे थे। अनिल चौधरी ने बताया कि दिवाले के दिन भी वह अनशन पर बैठे थे। उनके मिलने के लिए मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा और पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा अनशन स्थल पर उनसे मिलने पहुंचे। सभी ने अनशन खत्म करने का आग्रह किया था।

प्रधानमंत्री के सलाहकार से वार्ता के लिए बुलावा आया था। संगठन के कार्यकर्ता और आम लोगों ने अनशन स्थल पर बड़ी रंगोली बनाई। 1001 दीप जलाए गए। भारत माता का चित्र बनाया। बता दें कि 16 दिन से अनिल चौधरी अनशन पर बैठे हुए हैं, जबकि उनके समर्थक धरने पर बैठे हुए है। अब उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई है। करीब 12 किलो उनका वजन कम हो गया है। उनकी किडनी और लीवर में भी परेशानी हो रही है।

विवाद के बाद दीपावली पर कवि कुमार विश्वास ने जीता डॉ. पल्लव का दिल

संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। कवि डॉ. कुमार विश्वास ने दिवाली के दिन डॉ. पल्लव वाजपेयी के घर जाकर 8 नवंबर को हुई मारपीट की घटना पर खेद जताकर उनका दिल जीत लिया। उन्हें भगवान श्रीराम की मूर्ति भेंट करके दिवाली की शुभकामनाएं दीं। इस मुलाकात की डॉक्टर ने पुष्टि की और बताया कि वह करीब एक घंटे तक यहां रुके थे। डॉक्टर का कहना है कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई। उन्होंने किसी भी तरह केस वापस लेने का दबाव नहीं डाला।बता दें कि बीते 8 नवंबर को वसुंधरा स्थित अपने घर से अलीगढ़ जा रहे कुमार विश्वास के काफिले में शामिल सुरक्षाकर्मियों की कार को साइड देने के दौरान एक कार टकरा गई थी। इसे लेकर सुरक्षाकर्मियों और डॉक्टर में मारपीट हो गई थी। इस घटना के बाद कुमार विश्वास ने कार सवार एक व्यक्ति पर यूपी पुलिस के सिपाही और केंद्रीय सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए ट्विटर पर जानकारी दी थी। डॉ. पल्लव वाजपेयी इंदिरापुरम थाने में कुमार विश्वास के सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराइ थी हांलाकि इसमे कुमार विश्वास का जिक्र नहीं था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। घटना के अगले दिन सीआरपीएफ की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसके बाद सीआरपीएफ ने कुमार विश्वास की सुरक्षा में तैनात तीन सुरक्षाकर्मियों को हटाकर जांच बैठा दी गई थी।

लोनी व खोडा जल्द होंगे गाजियाबाद नगर निगम का हिस्सा

साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा व लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने साधे एक तीर से दो निशाने

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम की सीमा का जल्द ही विस्तार होगा। नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर और नगर पालिका परिषद लोनी को गाजियाबाद नगर निगम में शामिल किया जाएगा। इससे लोनी और खोड़ा में विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे। दोनों नगर पालिका परिषद के साथ कनावनी गांव को भी गाजियाबाद नगर निगम में शामिल करने का प्रस्ताव यूपी सरकार के पास भेजा गया है।

दिल्ली से सटे यह दोनों क्षेत्र लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस वजह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह और नगरआयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों जब रैपिडएक्स ट्रेन के उद्घाटन से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद पहुंचे थे तो निरीक्षण से पहले सीआइएसएफ गेस्टहाउस में उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी में पेयजल की समस्या के बारे में बताया। इसके साथ ही कूड़ा निस्तारण की समस्या के बारे में जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जवाब मांगा तो

संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान तभी हो पाएगा जब ये दोनों नगर पालिकाएं गाजियाबाद नगर निगम में शामिल हो जाएं। उसी वक्त उन्होंने अधिकारियों को प्रस्ताव जल्द से तैयार कर शासने को भेजने के निर्देश दिए। इसके बाद से नगरयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक मुख्यमंत्री के आदेश के अनुपालन हेतू अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की हैं।

गाजियाबाद नगर निगम में वर्तमान में 100 वार्ड है। खोड़ा और लोनी के शामिल होने से गाजियाबाद के वार्डों की संख्या 175 से लेकर 200 तक हो सकती है। ऐसा हुआ तो यह प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम होगा।

लेकिन एक साथ दो नगर पालिकाओं के नगर निगम में विलय के सियासी मायने में भी हैं।

लोनी और खोड़ा नगर पालिका परिषद को गाजियाबाद नगर निगम में शामिल करने के पीछे जो बड़ा सियासी दांव है उसके पीछे साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा और विधायक लोनी नंद किशोर गुर्जर की मांग है जिस पर शासन की ओर से कार्रवाई तेजी के साथ की जा रही है। इससे सियासी चहलकदमी भी बढ़ गई है। दरअसल लोनी नगर पालिका परिषद चेयरमैन की कुर्सी आरएलडी के पास है।

खोड़ा नगर पालिका परिषद की कुर्सी भी गैर बीजेपी चेयरमैन के पास है। लोनी चेयरमैन व आरएलडी नेता रंजीता धामा जहां नंद किशोर गुर्जर के लिए सियासी चुनौती हैं तो खोडा में पूर्व विधायक व सपा नेता अमर पाल शर्मा की चेयरमैन पत्नी मोहिनी शर्मा साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा के लिए चुनौती बन सकती है इसलिए दोनों ही विधायकों ने क्षेत्र के विकास का मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री के सामने मांग रखी की वह दोनों नगर पालिका परिषद को विलय नगर पालिका में कर दें। विपक्ष का सफाया करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ये सुझाव पसंद आया इसीलिए उन्होंने इस पर तत्काल प्रस्ताव तैयार कराने का निर्देश दिया।

अगर नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर और लोनी गाजियाबाद नगर निगम का हिस्सा बनती है तो हो सकता है कि बीजेपी का राजनैतिक दबदबा और बढ़ जाएगा। मगर सवाल यह उठने लगा है कि अगर तीनों ही निकायो को नगर निगम में मर्ज किया जाता है तो फिर जो पार्षद और निकाय चेयरमैन और नगर निगम में चुनी गई मेयर और पार्षदों का कार्यकाल क्या समय से पहले ही समाप्त कर नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे।

इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्टद्द नहीं है। वहीं सूत्रों का कहना है कि ऐसा संभव है कि प्रस्ताव के आधार पर शासन आपत्ति और सुझाव मांगने के बाद ही दोनों ही निकाय लोनी और खोड़ा नगर पालिका परिषद को नगर निगम में शामिल करने का फैसला लेगा। ऐसे में शासन नगर निगम के मौजूदा सदन को भंग भी कर सकता है।

डासना-मसूरी में सालों से चल रहा है गोमांस का काला कारोबार

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। डासना-मसूरी में गोमांस का काला कारोबार कई वर्षों से चल रहा है। पुलिस की नाक के नीचे लगातार क्षेत्र में गो-हत्या होती है। गोमांस देश के कई हिस्सों में भेजा जाता है।

जांच में सामने आया है कि लुधियाना में पकड़ा गया 10 टन गोमांस भी डासना की फर्म का है। इतने बड़े स्तर पर गो हत्या कर दूसरे शहर में गोमांस भेज दिया गया, लेकिन चेकिंग का दावा करने वाली पुलिस फेल रही। डासना-मसूरी क्षेत्र में गो हत्या कर तस्करी करने वाले धड़ल्ले से अपना काम करते हैं। यही वजह है कि यहां से लगातार गो तस्करी के मामले सामने आते हैं।

बीते साल 13 जनवरी को नोएडा पुलिस ने सेक्टर-62 में गो तस्कर जुनैद को एनकाउंटर के बाद पकड़ा था। आरोपित से डेढ़ हजार किलो गोमांस पकड़ा गया था।

इसी वर्ष 30 जून को तीन ट्रक गोमांस पकड़ा गया। 26 फरवरी को मसूरी के ननका गढ़ी गांव के पास खेत में पांच गाय की हत्या कर दी गई।

पुलिस का कहना है कि एक वर्ष में गो तस्करी के नौ मामले दर्ज किए गए जिनमं 31 आरोपित पकड़े गए और 15 क्विंट गोमांस बरामद किया गया।

ठूंस कर पशुओं को भरा जाता था

इन फैक्ट्रियों में आने वाले वाहनों में ठूंस ठूंस कर पशुओं को भरा जाता था। जिस कारण क्रूरता के साथ-साथ बच्चा पशु काटने के आरोप भी लगते रहे हैं। अल नफीस मीट फैक्ट्री पर आरोप था कि जमीन में बोर करके मीट फैक्ट्री का गंदा पानी डाला जाता है। जिस कारण इलाके का भूजल गंदा व खून युक्त हो गया था। क्षेत्र के लोगों ने लगभग 6 वर्ष पूर्व धरना प्रदर्शन किया था।

इतना ही नहीं, क्षेत्र में मुर्दा पशु ठेकेदारों पर भी आरोप है कि आरोपित स्वस्थ पशुओं को किसी न किसी रूप में जहर देकर मार देते हैं। बाद में मुर्दा पशुओं का मांस निकाल कर दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र में होटल में भेजा जाता है। डासना निवासी मोहसिन नाम के व्यक्ति पर भी मुर्दा पशुओं की ठेकेदारी की आड़ में करने का गंभीर आरोप लगा था।

पांच मीट फैक्टरी चलती थी

डासना-मसूरी क्षेत्र में पांच मीट फैक्ट्रियों द्वारा विदेशों को मीट निर्यात किया जाता था। इनमें भूड़ गढी स्थित अल-नफीस मीट फैक्ट्री, इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री, एनडी मीट फैक्ट्री, एसएस मीट फैक्ट्री तथा कल्लू गढ़ी स्थित ईगल मीट फैक्ट्री प्रमुख थीं। फिलहाल इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री संचालित है। दो सप्ताह पहले हाजी यासीन तोड़ी वालों की इस इंटरनेशनल मीट फैक्ट्री के साथ साथ मुंबई स्थित इनके कार्यालय पर भी ईडी का छापा पड़ा था। एसएस मीट फैक्ट्री पर भी एनजीटी ने नकेल कसते हुए लगभग दो महीने पूर्व सील बंद कर तालाबंदी कर दी है।

डीसीपी, ग्रामीण विवेक चंद्र यादव ने बताया कि स्थानीय पुलिस को गोकशी और गोतस्करों पर लगातार निगरानी और प्रभावी कार्रवाई के आदेश हैं। क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर गोहत्या किए जाने की जांच कराई जाएगी। स्थानीय स्तर पर आरोपित का साथ देने वालों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

कार्तिक मेले पर दिल्ली-लखनऊ रोड पर भारी वाहनों की नो एंट्री, रूट डायवर्जन होगा

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

हापुड़/अमरोहा। कार्तिक पूर्णिमा मेले पर दीपदान वाले दिन हापुड़ जिले की ब्रजघाट गंगानगरी में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर हापुड़ और अमरोहा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की और दिशा निर्देश दिए हैं।

सोमवार को ब्रजघाट में स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में हापुड़ डीएम प्रेरणा शर्मा, एसपी अभिषेक वर्मा और अमरोहा डीएम राजेश कुमार त्यागी, एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कार्तिक मेले को लेकर अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों जनपदों के अधिकारियों ने नेशनल हाईवे पर जाम न लगने को लेकर रूपरेखा तैयार की।

जिसमें तय हुआ कि भारी वाहनों का 23 नवंबर से रूट डायवर्जन किया जाएगा। इस दौरान अमरोहा और हापुड़ के डीएम ने एनएचएआई के अधिकारियों से कहा कि हाईवे पर सभी अवैध कटों को बंद किया जाए, जिससे मेले के दौरान कोई भी गलत दिशा में हाईवे पर वाहन न निकाल सके।

उन्होंने बताया कि हाईवे पर जाम का मुख्य कारण अवैध कट ही होती हैं। वहीं हापुड़ और अमरोहा एसपी ने भारी वाहनों के रूट डायवर्जन के लिए बनने वाले विकल्प मार्गों पर चर्चा की। इस दौरान हापुड़ एसपी ने कहा कि ब्रजघाट में आठ अस्थाई वाहन पार्किंग तैयार की जाएंगी, जिससे जाम की स्थिति न बन सके।

हाईवे पर किसी भी हालत में वाहनों को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। सीओ आशुतोष शिवम ने बताया कि रूट डायवर्जन के लिए चुने जाने वाले विकल्प मार्गों पर होर्डिंग लगाए जाएंगे। इस मौके पर एडीएम संदीप कुमार, एएसपी राजकुमार अग्रवाल, एसडीएम अंकित कुमार वर्मा, सीओ आशुतोष शिवम भी मौजूद रहे।

हाईवे पर लगातार होगी गश्त

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि मेले के दौरान नेशनल हाईवे पर अस्थाई थानों का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में गढ़ बदरखा फ्लाईओवर से लेकर ब्रजघाट गंगा पुल तक पुलिस पिकैट भी लगाई जाएंगी, तो लगातार हाईवे पर गश्त करेंगी।

खोडा में गंगाजल सप्लाई के लिए हो रहा अनशन

पांच साल से नेता दे रहे हैं सिर्फ झांसा

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

गाजियाबाद। खोड़ा में गंगाजल परियोजना का पानी लाने के लिए लंबे संघर्ष के बाद अब खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके दो साथी अनशन पर बैठ गए हैं। पिछले 5 वर्षों से लगातार खोड़ा कॉलोनी में गंगाजल परियोजना को लाने के लिए संगठन के लोग प्रयासरत हैं। खोड़ा के लोग पिछले पांच दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब वे खोड़ा में गंगाजल परियोजना का पानी आने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे।

यह है पूरा मामला

गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में गंगाजल परि-योजना की सप्लाई कराने के लिए खोड़ा के लोग पिछले 5 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि खोड़ा के नजदीक इंदिरापुरम, नोएडा, दिल्ली और मयूर विहार में गंगा परियोजना से जल आपूर्ति किया जाता है लेकिन खोड़ा कॉलोनी इस सुविधा से वंचित है। जिसके चलते लोगों को अवैध तरीके से बोरिंग कर पानी निकालना पड़ता है।

टीडीएस की मात्रा 700 से ऊपर

अनशन कर रहे दीपक जोशी ने बताया कि खोड़ा कॉलोनी में भूजल स्तर एक हजार फीट नीचे चला गया है। यहां पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है। कई जगह टीडीएस की मात्रा 700 से ऊपर है। जो कि पीने योग्य पानी नहीं है। इसके बावजूद लोग सबमर्सिबल का पानी पीने के लिए मजबूर है। धरना दे रहे दीपक जोशी का कहना है कि वह कई बार खोड़ा में गंगाजल परियोजना को लेकर प्रशासन से मिल चुके हैं लेकिन खाली वादों के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला है। जिससे अब वह थक चुके हैं और उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। आमरण अनशन

पर उन्हें 5 दिन हो गए हैं। दीपक जोशी के साथ आमरण अनशन पर बैठे अमरचंद ठेकेदार और मनोहर देवतला ने कहा कि जब तक खोड़ा में पानी नहीं आ जाएगा वे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे।

पानी के मुद्दे पर हुए चुनाव

खोड़ा के निवासी रविकांत भारद्वाज ने बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान खोड़ा में लड़े गए सभी चुनाव पानी के मुद्दे पर लड़े गए लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने खोड़ा में पानी लाने का प्रयास नहीं किया है। जिसके चलते अब आमरण अनशन का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा धरने पर बैठे दीपक जोशी को समर्थन देने के लिए खोड़ा कॉलोनी के सैकड़ों लोग पहुंचे है। इस दौरान कई संस्थाओं से भी इन लोगों को समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उनके साथ हरिओम, मेघानंद, गुलाब सिंह गौतम, असलम खान सहित सैकड़ों लोग धरना दे रहे हैं।

दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री पर केजरीवाल सरकार और प्रशासन आमने-सामने

विशेष संवाददाता @visheshkhabar.in

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर लगे कथित भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और प्रशासन आमने-सामने की स्थिति में है। सीएस के बेटे की कंपनी को 315 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के आरोप पर तकरार जारी है। मंगलवार को विजिलेंस मंत्री आतिशी ने 650 पन्ने की प्राथमिक एक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। इससे पहले सोमवार को डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव ने बेटे की कंपनी को 850 करोड़ का नाजायज फायदा पहुंचाया है। मामला संज्ञान में तब आया जब द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण पर रिपोर्ट आई।

3 दिन में सौंपी रिपोर्ट

विजिलेंस मंत्री आतिशी ने 11 नवंबर को जांच शुरू की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में आतिशी से रिपोर्ट मांगी थी। मंत्री आतिशी ने दिल्ली के विजिलेंस विभाग के निदेशक और डिविजनल कमिश्नर को पत्र लिखकर उनसे इस संबंध में सभी फाइलें मांगी थी। मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे से जुड़ी एक कंपनी को 315 करोड रुपए का फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है.आरोप है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण में हेरफेर कर उन्होंने अपने बेटे की कंपनी को 315 करोड रुपए का फायदा पहुंचाया है।

बीते शुक्रवार को इसकी शिकायत मिलते ही मुख्यमंत्री ने विजिलेंस मंत्री को जांच के आदेश दिए थे। ह-लांकि, इस पर मुख्य सचिव ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। सोमवार को जिला दिल्ली के मंडलायुक्त अश्वनी कु-मार ने भी प्रेस कांफ्रेंस कर सभी आरोपों को निराधार बताया था।

डिवीजनल कमिश्नर का दावा जानें क्या है मामला:

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने डीएम को जमीन का मुआवजा बढ़ाने के लिए कहा था। पिछले तीन जिला अधिकारी ने जमीन का मुआवजा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। नरेश कुमार के मुख्य सचिव बनने के 40 दिनों के बाद हेमंत कुमार साउथ वेस्ट जिले के डीएम बने और उन्होंने जमीन की मुआवजा राशि 41.50 करोड़ से बढ़कर 353 करोड़ रुपए करने के आदेश दिए। कथित मामले में कंपनी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास 2015 में जमीन मात्र 75 लाख में खरीदी थी। अब महंगे रेट पर भूमि अधिग्रहण हुआ, जिससे कंपनी को 850 करोड़ का नाजायज फायदा हुआ है। मुख्य सचिव ने बेटे की कई अन्य कंपनियां को भी सरकारी ठेके दिये। इन कंपनियों की भी जांच की सिफारिश की बात कही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक विनीतकांत पाराशर द्वारा विवेक पब्लिशर ए-16, सेक्टर 7 नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से मुद्रित कराकर सैकेंड ए-288 नेहरूनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-202001 से प्रकाशित किया। संपादक-विनीतकांत पाराशर